Page-01_Layout 1 3/26/2025 1:12 AM Page 1

■ वर्ष-17 ■ अंक-65 ■ पृष्ठ-8 ■ मूल्य : 1 रुपए

नई दिल्ली, बुधवार, 26 मार्च, 2025

newdibyabharat@gmail.com

केंद्र ने नक्सल विरोधी सिविक एक्शन प्रोग्राम के लिए सीएपीएफ... पृष्ठ-3

दिव्य भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

दिल्ली के विकास और प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा... पृष्ठ-7

रेखा गुप्ता ने पेश किया 1 लाख करोड़ का बजट

महिला समृद्धि से लेकर आयुष्मान योजना का ऐलान

रमाकान्त पाण्डेय

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री एवं वित्त विभाग संभाल रही रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के बजट की तुलना में यह 31.5 फीसदी अधिक है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में दिल्ली का बजट 78 हजार 800 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में घटकर सिर्फ 76 हजार करोड़ रुपये रह गया था। हालांकि, पहली बार अगामी वित्त वर्ष के लिए दिल्ली को 1 लाख करोड़ रुपये का बजट मिला है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि है।

बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन को बताया कि सरकार को 68,700 करोड़ रुपये कर से प्राप्त होगा। वहीं 750 करोड़ रुपये कर के अतिरिक्त कमाई से, 15 हजार करोड़ रुपये लघु अवधि कर्ज से और 1 हजार करोड़ रुपये सड़क निधि से आएंगे। इसके अलावा 4,128 हजार करोड़ रुपये केंद्र सरकार की योजनाओं से आएंगे और 7,341 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से मदद के रूप में लिए जाएंगे।

रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए मातृत्व वंदन परियोजना के लिए 210 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को एकमुश्त 21 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए 50 हजार अतिरिक्त कैमरे लगाए जाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने बजट भाषण में दिल्ली की जनता के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के इंश्योरेंस कवर का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 5 लाख रुपये के कवर के साथ दिल्ली सरकार लोगों को 5 लाख रुपये का टॉप-अप देगी। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इसके लिए 2144 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के बजट में महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे।

रेखा गुप्ता ने दिल्ली की सड़कों को सुधारने, विकास को रफ्तार देने, बुनियादी ढांचों को सुधारने के लिए बजट में 28 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 हजार करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय से दिल्ली में सड़क, पुल, जल निकासी, ट्रांसपोर्ट और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में व्यापक सुधार होगा। उन्होंने कहा कि यह बजट दिल्ली को एक स्मार्ट और आधुनिक शहर में बदलने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

हर घर साफ पानी और सीवर सिस्टम अपग्रेडमुख्यमंत्री ने हर घर साफ पानी और सीवर सिस्टम के अपग्रेड की बात कही। जल आपूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए 9 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इससे नई जल पाइपलाइन बिछाई जाएंगी, सीवर लाइनों का विस्तार होगा और हर नागरिक को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिलेगी।

अटल कैंटीन से जरुरतमंदों को सस्ता और पौष्टिक भोजनमुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 100 करोड़ के बजट से 100 झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में अटल कैंटीन की स्थापना कर जरुरतमंदों को सस्ता और पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाएगा। भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य पर 100 अटल कैंटीन खोली जाएंगी, जहां कम कीमत पर पौष्टिक भोजन मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि पूरे 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के बजट को ऐतिहासिक बताते हुए दिल्ली में एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है।

जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंची तीन सदस्यीय जांच कमेटी

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के तीन सदस्यों की कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। तीन सदस्यीय कमेटी मंगलवार को तकरीबन 45 मिनट जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास 30, तुगलक क्रेसेंट पर रही। कमेटी ने उस कमरे का भी मुआयना किया, जिसमें 14 मार्च को आग लगी थी। इसके बाद टीम यहां से चली गई।

दरअसल, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर 14 मार्च को आग लगने के बाद अग्निशमन विभाग ने कैश बरामद किया था। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश पर जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्य वापस ले लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस अनु शिवरामन को रखा गया है।

सौ दिवसीय अभियान ने टीबी मुक्त भारत के लिए तैयार किया एक मजबूत आधार : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का एक लेख साझा करते हुए कहा कि हाल ही में संपन्न 100-दिवसीय सघन टीबी मुक्त भारत अभियान ने टीबी मुक्त भारत के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पोस्ट में कहा, टीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई में उल्लेखनीय प्रगति देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हाल ही में संपन्न 100-दिवसीय सघन टीबी मुक्त भारत अभियान पर महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसने टीबी मुक्त भारत के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है, इसे अवश्य पढ़ें।

नड्डा ने एक्स पोस्ट में कहा कि इस विश्व क्षय रोग दिवस पर मैं इस बात पर बहुत गर्व के साथ विचार करता हूं कि भारत टीबी के खिलाफ लड़ाई में किस तरह से अपनी रणनीति को फिर से लिख रहा है। हाल ही में संपन्न 100-दिवसीय सघन टीबी मुक्त भारत अभियान ने न केवल नवाचार की शक्ति का प्रदर्शन किया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि समुदायों को संगठित करना कार्यक्रम संबंधी दृष्टिकोण को बदलने जितना ही महत्वपूर्ण है। मामलों का पता लगाने में तेजी लाकर, मृत्यु दर को कम करके और नए संक्रमणों को रोककर, इस अभियान ने टीबी मुक्त भारत के लिए एक मजबूत नींव रखी है। भारत सिर्फ.टीबी से नहीं लड़ रहा है, हम इसे हरा रहे हैं।

नड्डा ने लेख में कहा कि यह अभियान 7 दिसंबर, 2024 को टीबी के मामलों का पता लगाने, मृत्यु दर को कम करने और नए मामलों को रोकने के उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया था। 100-दिवसीय सघन टीबी मुक्त भारत अभियान ने टीबी का समय रहते पता लगाने के लिए अत्याधुनिक रणनीतियां शुरू कीं, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि बिना लक्षण वाले लोगों की भी पहचान की गई- जिनका अन्यथा निदान नहीं हो पाता और उनका इलाज किया गया। पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों को सीधे उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के पास ले जाया गया, जिनमें मधुमेह, धूम्रपान करने वाले, शराब पीने वाले, एचआईवी से पीड़ित, बुजुर्ग, कम बीएमआई वाले और टीबी रोगियों के घरेलू संपर्क शामिल थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित एक्स-रे ने संदिग्ध टीबी मामलों को तुरंत चिह्नित किया और स्वर्ण-मानक न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट (एनएएटी) का उपयोग कर पुष्टि की गई। इन प्रयासों ने सुनिश्चित किया कि संक्रामक मामलों की पहचान की गई और उनका जल्दी से जल्दी इलाज किया गया, जिससे संक्रमण पर लगाम लगी और लोगों की जान बच गई। यह अभियान देश के कोने-कोने तक पहुंचा, जिसमें कमजोर आबादी वाले 12.97 करोड़ लोगों की जांच की गई। इस गहन प्रयास के कारण 7.19 लाख टीबी रोगियों की पहचान की गई, जिनमें से 2.85 लाख मामले बिना लक्षण वाले थे।

नड्डा ने अपने लेख के माध्यम से कहा है कि 100 दिवसीय अभियान अभी शुरूआत है। भारत इन प्रयासों को पूरे देश में बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर नागरिक चाहे वे कहीं भी रहते हों, को आधुनिक निदान, गुणवत्तापूर्ण उपचार और अटूट सामुदायिक समर्थन तक पहुंच प्राप्त हो। जिस तरह भारत ने कोविड-19 परीक्षण को तेजी से बढ़ाया, उसी तरह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अगली पीढ़ी के टीबी निदान में निवेश कर रहा है ताकि अंतिम मील तक तेज और अधिक सटीक परीक्षण लाया जा सके।

एक राष्ट्र-एक चुनाव संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ा

नई दिल्ली, (हि.स.)। लोकसभा ने मंगलवार को एक राष्ट्र-एक चुनाव से जुड़ी संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल मानसून सत्र तक के लिए बढ़ा दिया है। समिति को इस संबंध में लोकसभा में पेश दो विधेयक विचार के लिए भेजे गए हैं। 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024: यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है।केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2024: यह विधेयक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रावधान करता है।

संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने लोकसभा में आज इस संबंध में प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि राज्यसभा से एक सदस्य को समिति में शामिल किया गया है।

देशभर में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने से जुड़े विधेयकों पर विचार करने के लिए शीतकालीन सत्र में समिति का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल बजट सत्र तक ही था। समिति के सदस्यों का मानना है कि इससे जुड़े कानून के लिए हितधारकों, राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों से व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता है, जिसके कारण विचार हेतु काफी समय चाहिए।

संविधान से खिलवाड़ कर मुस्लिम तुष्टिकरण कर रही कांग्रेस : चुग

- गांधी परिवार की चाटुकारिता में डूबे डी.के. शिवकुमार और जयराम

आलोक पाण्डेय

चंडीगढ़/दिल्ली। कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन पर निशाना साधते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरूण चुग ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से तुष्टिकरण की राजनीति करती आई है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने खुलेआम घोषणा की है कि कांग्रेस मुस्लिमों को सरकारी ठेकों में आरक्षण देने के लिए संविधान तक में संशोधन करेगी। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा संविधान में बदलाव की ऐसी बात कहना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसे नेता को तत्काल उपमुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किया जाएगा या नहीं?

चुग ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गांधी परिवार के महापरिक्रमावादी नेता जयराम रमेश ने राज्यसभा में भाजपा नेताओं के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का नोटिस देकर शिवकुमार के बयान का बचाव करने की शर्मनाक कोशिश की है। पहले डीके शिवकुमार गांधी परिवार को खुश करने के लिए संविधान बदलने तक की बात करते हैं, फिर उन्हीं को बचाने के लिए जयराम रमेश सामने आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार की चाटुकारिता के अलावा और कोई सिद्धांत नहीं बचा है।

चुग ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में तुष्टिकरण की राजनीति की शुरूआत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी, जिन्होंने मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में पलट दिया था। यही तुष्टिकरण बाद में मनमोहन सिंह के उस बयान में भी झलका, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। कांग्रेस नेता बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो और संविधान की प्रति जेब में लेकर घूमने का दिखावा करते हैं, लेकिन सत्ता के लालच में संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आते।

तरूण चुग ने यह भी आरोप लगाया कि हिंदुओं के प्रति कांग्रेस की नीति हमेशा से भेदभावपूर्ण रही है, और इसमें भविष्य में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा उन्होंने कहा की केवल कर्नाटक ही नहीं, बल्कि तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार मुस्लिमों को आरक्षण सूची में डालकर चुपचाप पिछला दरवाजा खोलकर आरक्षण दे रही है। राहुल गांधी, जो स्वयं को संविधान के रक्षक बताते हैं, इस गंभीर मामले पर अब मौन क्यों हैं? चुग ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही राष्ट्रीय हितों को ताक पर रखकर तुष्टिकरण की नीति अपनाई है। यही वह पार्टी है जिसने धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा स्वीकार किया और फिर विभाजन के बाद भी धार्मिक तुष्टिकरण पर देश चलाने का कुप्रयास कर रही है, मुस्लिम आरक्षण के माध्यम से एससी एसटी एवं ओबीसी भाइयों के आरक्षण एवं संसाधनों को कांग्रेस एवं इंडी गठबंधन मुस्लिमो को देना चाहती है।

ईद से पहले राजधानी में शुरू हुआ भाजपा का सौगात-ए-मोदी अभियान

नई दिल्ली, (हि.स.)। देश के मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की सौगात देने के मकसद से भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभियान सौगात-ए-मोदी मंगलवार को राजधानी दिल्ली में शुरू किया गया। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने गालिब अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में इस अभियान की शुरूआत की। कार्यक्रम में भाजपा महामंत्री और मोर्चा के प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी भी मौजूद रहे।

इस दौरान उन्होंने कई लोगों को सौगात-ए-मोदी के तहत निजामुद्दीन क्षेत्र में उपहार बांटे। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 32 लाख गरीब मुस्लिम परिवार बिना किसी कठिनाई के त्योहार मना सकें। इस अभियान के तहत 32,000 अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ता जरूरतमंदों तक पहुंचने के लिए देशभर की 32,000 मस्जिदों के साथ सहयोग करेंगे।

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने मीडिया को बताया कि रमजान के पवित्र महीने और ईद, गुड फ्राइडे, ईस्टर, नौरोज और भारतीय नववर्ष जैसे आगामी अवसरों के दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा सौगात-ए-मोदी अभियान के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगा। जिला स्तर पर ईद मिलन समारोह भी आयोजित किए जाएंगे।

सौगात-ए-मोदी ईद किट पर भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी का विकास एजेंडा कभी भी वोटों के लिए नहीं रहा है। पिछले 11 सालों में उन्होंने समाज के आखिरी पायदान पर खड़े लोगों के जीवन में खुशिहाली लाने का काम किया है। विकास के मामले में उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। यहां तक ??कि जो लोग मोदी को वोट देने से कतराते हैं, वे भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मोदी ने अपने वादे पूरे किए हैं। सौगात-ए-मोदी किट के जरिए गरीब मुसलमानों को जरूरी सामान मुहैया कराया जाएगा। इस किट में सेवइयां, आटा, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और चीनी जैसे खाने के सामान के साथ कपड़े भी होंगे।

Page-02_Layout 1 3/26/2025 1:15 AM Page 1

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करने के बाद सत्र को संबोधित करते हुए।

देश में निर्मित पहली एमआरआई मशीन दिल्ली के एम्स में लगेगी

नई दिल्ली, (हि.स.)। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी 'मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग'(एमआरआई) मशीन विकसित की है। इसे जल्दी ही दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में स्थापित किया जाएगा। इसी साल अक्टूबर में यह मशीन काम करना शुरू कर देगी। फिलहाल, इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा लेकिन अक्टूबर से इसका इस्तेमाल आधिकारिक तौर पर शुरू किया जाएगा। इस मशीन से कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियों की जांच सस्ती हो सकेगी।

मंगलवार को इस संबंध में एम्स और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाला सोसायटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (समीर आरएनडी) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस कदम का उद्देश्य उपचार लागत और आयातित चिकित्सा उपकरणों पर निर्भरता को कम करना है, क्योंकि वर्तमान में 80-85 प्रतिशत उपकरण आयात किए जाते हैं। स्वदेशी एमआरआई मशीन भारत को चिकित्सा प्रौद्योगिकी में अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी।

इस मौके पर एम्स के निदेशक डॉ. एम श्रीनिवास ने कहा कि संस्थान आज अपनी पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन स्थापित कर रहा है। इसका लाभ यह होगा कि हम सर्वोत्तम वैश्विक उपकरणों का उपयोग करते हुए, स्वदेशी मशीन के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दे सकेंगे। इससे मशीन बनाने वाली कंपनी समीर आरएनडी और संबंधित संस्थानों को आवश्यक परिवर्तन करने में मदद मिलेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हमारे पास दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उपकरण हैं।

एमआरआई स्कैन के लिए शक्तिशाली चुंबकों, रेडियो किरणों और कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, जिसकी मदद से शरीर की जानकारी को विस्तृत तस्वीरों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इस परीक्षण का उपयोग हड्डियों, मांसपेशियों, मस्तिष्क पदार्थ, जोड़ों, धमनियों और बहुत कुछ को देखने के लिए किया जा सकता है। एमआरआई सबसे कम हानिकारक परीक्षणों में से एक है और इसका उपयोग दुनिया भर के डॉक्टर सटीक निदान और उपचार योजना बनाने के लिए करते हैं।

दिल्ली की महिलाओं के लिए बसों में फ्री यात्रा के लिए कार्ड बनाएंगे : मुख्यमंत्री

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट भाषण में कहा कि दिल्ली की सभी फ्री की योजनाएं चालू रहेंगी। इसके लिए बजट में धन आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की महिलाओं के लिए बसों में फ्री यात्रा के लिए कार्ड बनाएंगे। इसके बाद महिलाओं को टिकट लेने कोई जरूरत नहीं होगी। इससे टिकट के नाम पर होने वाला भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा।

दिल्ली में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बस बेड़ा है, जिसमें 2,152 इलेक्ट्रिक बसें हैं। इसमें डीटीसी के तहत 1,752 इलेक्ट्रिक बसें और डिम्ट्स क्लस्टर योजना के तहत 400 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025-26 तक बेड़े में 5000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने की उम्मीद है और इसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस बेड़ा हासिल करना है।

डीएमआरसी 289 स्टेशनों के साथ 394.25 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क का संचालन कर रही है। चरण-4 में 03 प्राइआरिटी कॉरिडोर का 60 फीसद काम पहले ही पूरा हो चुका है। इसके साथ ही चरण-4 के बैलन्स्ट 03 कॉरिडोर अर्थात लाजपत नगर - साकेत जी ब्लॉक, इंद्रलोक - इंद्रप्रस्थ, रिठाला बवाना नरेला - नाथूपुर (कुंडली) का काम 2025-26 में शुरू किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो के लिए 2929.66 करोड़ का आवंटन किया गया है। भारत सरकार के वित्त पोषण से राजधानी में शहरी परिवहन परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। इन केंद्रीय वित्त पोषण परियोजनाओं के लिए 1,000 करोड़ का आवंटन किया गया। दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 12,952 करोड़ का बजट परिव्यय का लक्ष्य रखा गया है।

पुलिस ने वांछित बदमाश को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हत्या के प्रयास, ड्रग्स तस्करी और डकैती के मामले में वांछित बदमाश सौरव उर्फ गुल्लन को

गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला आरोपित ने चौथी कक्षा तक पढ़ाई की है और वह शादीशुदा है और उसका एक बच्चा है। आरोपित 15 से अधिक मामलों में शामिल रहा है क्राइम ब्रांच के डीसीपी विक्रम सिंह ने मंगलवार को बताया कि क्राइम ब्रांच ने वांछित बदमाशों को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया हुआ है।

विकसित दिल्ली की दिशा में यह बजट एक मील का पत्थर : खंडेलवाल

नई दिल्ली, (हि.स.)। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक क्षेत्र से सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने दिल्ली सरकार के वित्त वर्ष 2025-26 के बजट को संतुलित, जनहितकारी और विकासोन्मुखी बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट सर्वस्पर्शी है, जिसमें दिल्ली के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। विकसित दिल्ली की दिशा में यह बजट एक मील का पत्थर है।

कैट के महामंत्री खंडेलवाल मंगलवार को दिल्ली सरकार के वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये के प्रस्तुत बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने एक बयान में कहा कि यह बजट दिल्ली की आर्थिक प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार ने व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित बजट प्रस्तुत किया है। सांसद खंडेलवाल ने कहा कि बजट में व्यापार और उद्योगों को सशक्त बनाने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं, जिससे दिल्ली के व्यापारियों और उद्यमियों को लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने व्यापार एवं उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां बनाने और ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन की घोषणा की है। इससे दिल्ली में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तथा व्यापार करना आसान होगा। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़ा आवंटन, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए ठोस कदम तथा परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई परियोजनाएं दिल्ली में विकास को गति देगी। सांसद खंडेलवाल ने यमुना की सफाई के लिए धन आवंटन करने को यमुना को साफ करने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में सही कदम बताया।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया, जो पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के बजट की तुलना में 31.5 फीसदी अधिक है।

आज का राशिफल

मेष राशि-कार्य लाभ, आशानुकूल सफलता का हर्ष होगा, रुके कार्य अवश्य बनेंगे।

वृष राशि-योजना पूर्ण होंगी, शुभ समाचार से मन प्रसन्न हो, सोचे हुए कार्य अवश्य बन जायेंगे।

मिथुन राशि-कार्य व्यवासय में थकावट बेचैनी, कुछ सफलता के साधन अवश्य ही बन जायेंगे।

कर्क राशि-दैनिक व्यवसाय गति मंद रहे, असमर्थता का वातावरण बना ही रहेगा।

सिंह राशि-आलोचना से बचिये, कार्य-कुशलता से पूर्ण संतुष्टि तथा संतोष बना ही रहेगा।

कन्या राशि-भोग-ऐश्वर्य में समय बीते, शारीरिक थकावट व बेचैनी कार्य में बढ़ेगी, ध्यान रखें।

तुला राशि-मित्र वर्ग विशेष फलप्रद रहे, आशानुकूल सफलता से संतोष होगा।

वृश्चिक राशि-मित्र वर्ग विशेष फलप्रद रहे, कार्य में सफलता प्राप्त होगी, रुके कार्य अवश्य बनेंगे।

धनु राशि-तनावपूर्ण वातावरण चलता ही रहेगा तथा सुखवर्धक योग अवश्य ही बनेंगे।

मकर राशि-कार्यवृत्ति में सुधार, सामाजिक कार्य में मान-प्रतिष्ठा अवश्य ही बनेगी।

कुंभ राशि-कार्य-व्यवसाय गति मंद, चोर आदि का भय होगा तथा मानसिक तनाव बनेगा।

मीन राशि-आशानुकूल सफलता का हर्ष, बिगड़े कार्य की योजना अवश्य ही बनेगी।

-अम्बुजा तिवारी

गालिब एकेडमी में सौगात-ए-मोदी किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन

नई दिल्ली, (हि.स.)। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जरिए हजरत निजामुद्दीन स्थित गालिब एकेडमी में सौगात-ए-मोदी किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी द्वारा चिन्हित किए गए 200 जरूरतमंद लोगों को सौगात-ए-मोदी किट वितरित की गई।

इस मौके पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनीस अब्बासी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसएम अकरम, सूफी संवाद अभियान के राष्ट्रीय प्रभारी डॉ असलम, यासिर जिलानी, सौगात-ए-मोदी अभियान दिल्ली के प्रभारी इरफान सलमानी देहलवी, सह प्रभारी इमतियाज अहमद, कमाल बाबर, बबलू मंसूरी, फहीम सैफी, नईम सैफी, फैसल मंसूरी सहित बड़ी संख्या में मोर्चे के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

गौरतलब है कि अल्पसंख्यक मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में सौगात-ए-मोदी अभियान के जरिए ईद पर 32 लाख जरूरतमंदों तक पहुंचने की योजना बनाई है। इस मौके पर मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सफल नेतृत्व में भारत सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। मोर्चे के 32 हजार पदाधिकारी 32 हजार मस्जिदों से सम्पर्क कर 32 लाख जरूरतमंदों को सौगात-ए-मोदी किट के माध्यम से उपहार स्वरूप जरूरत की चीजें पहुंचाएगा। किट में खाद्य सामग्री के अलावा कपड़े, सेवईं, खजूर, मेवे और चीनी शामिल है। महिलाओं के लिए किट में सलवार-सूट का कपड़ा होगा, जबकि पुरुषों के लिए कुर्ता-पायजामा शामिल है। भाजपा का यह अभियान गरीब और जरूरतमंद मुस्लिम परिवारों को सहायता प्रदान करने के साथ-साथ समाज के विभिन्न वर्गों तक अपनी पहुंच बढ़ाने का भी एक प्रयास माना जा रहा है।

उप्र विधानसभा अध्यक्ष ने दिल्ली सरकार के बजट को दिल्ली की आत्मा बताया

नई दिल्ली, (हि.स.)। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दिल्ली सरकार के बजट को दिल्ली की आत्मा बताया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष मंगलवार को दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन यहां अतिथि के रूप में बजट सत्र देखने पहुंचे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सतीश महाना का स्वागत किया और कहा कि उनकी उपस्थिति से दिल्ली विधानसभा गौरवान्वित महसूस करती है।

सतीश महाना ने दिल्ली विधानसभा के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह वही सदन है, जहां संसद की शुरूआती कार्रवाई हुआ करती थी, मेरी इच्छा थी कि मैं दिल्ली विधानसभा आऊं और मुझे आकर प्रसन्नता हुई।

दिल्ली सरकार के वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पर उन्होंने कहा कि आज नई सरकार का पहला बजट था।

पिछले वर्ष से लगभग 31 फीसद ज्यादा बड़ा इस बार बजट का आकार है। पूंजीगत व्यय पर विशेष महत्व दिया गया है। दिल्ली की आम जनता के उत्थान के लिए और यमुना की सफाई के लिए ये बजट है। ये बजट दिल्ली की आत्मा का बजट है। मुझे विश्वास है कि यह बजट जनकल्याणकारी सिद्ध होगा।

सूडोकु नवताल- 7381

मध्यम

		5			3			
	2			9	5			
9						6		
			9				3	5
	6						7	
4	8				1		6	2
		7						3
			2	4			9	
			8			2		

Jagrutidaur.com, Bangalore

- *प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.*
- *प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.*
- *पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते .*
- *पहेली का केवल एक ही हल है.*

सूडोकु नवताल -7380 का हल

2	7	6	4	9	5	8	1	3
5	8	1	7	2	3	9	6	4
9	3	4	8	1	6	2	5	7
6	5	9	2	4	8	3	7	1
8	4	7	9	3	1	6	2	5
1	2	3	5	6	7	4	9	8
3	6	5	1	8	2	7	4	9
7	9	2	3	5	4	1	8	6
4	1	8	6	7	9	5	3	2

दैनिक पंचांग

26 मार्च 2025 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

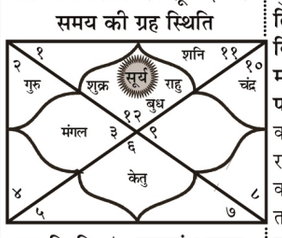

ग्रह स्थिति		लग्नारंभ समय	
सूर्य	मीन में	मेष	06.58 बजे से
चंद्र	मकर में	वृष	08.38 बजे से
मंगल	मिथुन में	मिथुन	10.37 बजे से
बुध	मीन में	कर्क	12.50 बजे से
गुरु	वृष में	सिंह	15.06 बजे से
शुक्र	मीन में	कन्या	17.18 बजे से
शनि	कुंभ में	तुला	19.29 बजे से
राहु	मीन में	वृश्चिक	21.43 ब.से
केतु	कन्या में	धनु	23.59 बजे से
राहुकाल	12.00 से 1.30 बजे तक	मकर	02.05 बजे से
		कुंभ	03.51 बजे से
		मीन	05.24 बजे से

बुधवार 2025 वर्ष का 85 वा दिन **दिशाशूल** उत्तर **ऋतु** बसंत। **विक्रम संवत्** 2081 **शक संवत्** 1946 **मास** चैत्र (दक्षिण भारत में फाल्गुन) **पक्ष** कृष्ण **तिथि** द्वादशी 01.43 बजे रात्र को समाप्त। **नक्षत्र** धनिष्ठा 02.30 बजे रात्र को समाप्त। **योग** सिद्ध 12.25 बजे को समाप्त। **करण** कौलव 14.50 बजे तदनन्तर तैतिल 01.43 बजे रात्र को समाप्त। **चन्द्रायु** 24.0 घण्टे **रवि क्रान्ति** उत्तर 02° 13' **सूर्य** उत्तरायन **कलि अहर्गण** 1872295 **जूलियन दिन** 2460760.5 **कलियुग संवत्** 5125 **कल्पारंभ संवत्** 1972949123 **सृष्टि ग्रहारंभ संवत्** 1955885123 **वीरनिर्वाण संवत्** 2551 **हिजरी सन्** 1446 **महीना** रमजान **तारीख** 25 **विशेष** वैष्णव पापमोचनी एकादशी।

दिन का चौघड़िया				रात का चौघड़िया			
लाभ	05.54	से 07.22	बजे तक	उद्वेग	05.41	से 07.12	बजे तक
अमृत	07.22	से 08.51	बजे तक	शुभ	07.12	से 08.44	बजे तक
काल	08.15	से 10.19	बजे तक	अमृत	08.44	से 10.16	बजे तक
शुभ	10.19	से 11.47	बजे तक	चर	10.16	से 11.47	बजे तक
रोग	11.47	से 01.16	बजे तक	रोग	11.47	से 01.19	बजे तक
उद्वेग	01.16	से 02.44	बजे तक	काल	01.19	से 02.51	बजे तक
चर	02.44	से 04.12	बजे तक	लाभ	02.51	से 04.23	बजे तक
लाभ	04.12	से 05.41	बजे तक	उद्वेग	04.23	से 05.54	बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अत: आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। Jagrutidaur.com, Bangalore

शब्द पहेली - 8443

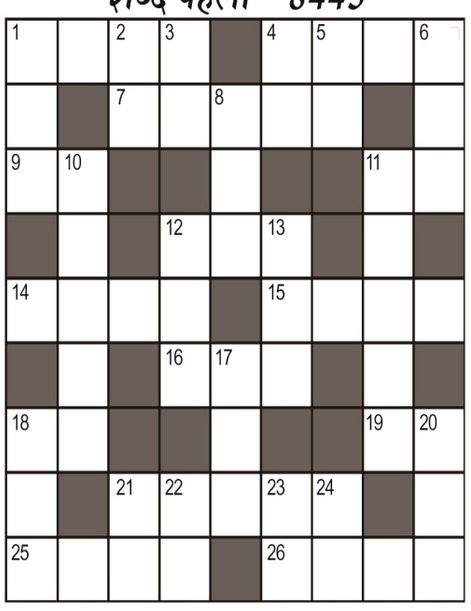

बाएँ से दाएँ

1. आदत,स्वभाव-4
4. सुरक्षित-4
7. जरुरतमंद-5
9. भीगा हुआ-2
11. मक्का-मदीना की यात्रा-2
12. सोना,धतुरा-3
14. धक्का देना-4
15. खानाबदोश,बंजारा-4
16. अंधेरा,अंधकार-3
18. खामी,बुरी आदत-2
19. ईसाई साध्वी-2
21. नायक का विलोम-5
25. करिश्मा,करामात-4
26. महीन व मंहगे कपड़े का एक प्रकार -4

ऊपर से नीचे

1. अंग्रेज,विदेशी-3
2. लीन,मगन-2
3. पैंदा,तला-2
4. रिश्तेदार-2
5. थूक,लेस-2
6. तहजीब,सलीका-3
8. देह,काया-3
10. टोने-टोटकों वाली किताब-5
11. स्वदेशवासी -5
12. कपड़े की दीवार-3
13. अनुमान,आकलन-3
17. राजी करना-3
18. चश्मा-3
20. अनुकृति-3
21. पत्र,चिट्ठी-2
22. होठ,अधर-2
23. मृत्यु देवता,यमराज-2
24. बीता हुआ दिन-2

शब्द पहेली -8442 का हल

■	त	ल	ब	■	ट	म	ट	म
प	■	■	द	स्त	क	■	■	हा
र	■	ना	नी	■	ला	श	■	ज
ख	ल	ना	य	क	■	व	त	न
■	ल	■	त	■	ना	■	री	■
म	ना	ही	■	ह	क	ब	का	ना
हा	■	ना	क	■	क	ल	■	यि
व	■	■	स	पा	ट	■	■	का
त	व	वा	र	■	ना	ह	क	■

Jagrutidaur.com, Bangalore

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सुरक्षा बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।

Page-03_Layout 1 3/26/2025 1:16 AM Page 1

पटना। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर इफ्तार पार्टी में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।

लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक

नई दिल्ली, (हि.स.)। राज्यसभा ने मंगलवार को आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पास कर चुकी है। इसके साथ ही विधेयक को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिल गई। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा प्रबंधन (संशोधन)विधेयक-2024 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सदस्यों को आश्वस्त कराया कि इससे संघीय ढांचे को नुकसान नहीं होगा। सरकार की मंशा आपदा की लड़ाई में केंद्र, राज्य सरकार, पंचायत और प्रत्येक नागरिक को जोड़ने की है। उन्होंने कहा, अब, चिंताओं को व्यक्त किया जा रहा है कि शक्ति का केंद्रीकरण होगा। यदि आप पूरे बिल को ध्यान से पढ़ते हैं तो कार्यान्वयन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिला आपदा प्रबंधन के साथ है जो राज्य सरकार के अधीन है। इसलिए कहीं भी संघीय संरचना को नुकसान पहुंचाने की कोई संभावना नहीं है। अमित शाह ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य आपदा प्रबंधन से जुड़ी लड़ाई को प्रतिक्रिया से आगे बढ़कर समय-पूर्व बचाव और उससे भी आगे जाकर इसमें नवाचार और सहभागिता को शामिल करना है। एनडीआरएफ पर लोगों के विश्वास का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, आज एनडीआरएफ की 16 बटालियन काम कर रही हैं। यह आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि एनडीआरएफ के भगवा रंग के कपड़े लोगों को यह विश्वास दिलातें हैं कि यह आ गए, अब हम बच जाएंगे। गृहमंत्री ने इस दौरान आपदा राहत पर पक्षपात के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग ने आपदा राहत को लेकर एक वैज्ञानिक तंत्र तैयार किया है। मोदी सरकार इस तंत्र के तहत कार्य कर रही है और किसी को भी काम या ज्यादा नहीं दिया गया है। इस दौरान गृहमंत्री ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्तर पर बढ़ती साख का उल्लेख किया। गृहमंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में हम राष्ट्रीय स्तर से ग्लोबल पावर बनकर उभरे हैं। भारत की पहल पर बने आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन के आज 42 देश और 7 अंतरराष्ट्रीय संगठन सदस्य हैं। यह विधेयक भारत की इस सफल कहानी को लंबे समय तक बनाने रखने के लिए लाया गया है। शाह ने आंकड़ों की जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2004-14 में एसडीआरएफ का बजट सिर्फ 38 हजार करोड़ था, जबकि मोदी सरकार में वर्ष 2014-24 में बढ़कर एक लाख 24 हजार करोड़ हो गया। इसी तरह एनडीआरएफ का बजट वर्ष 2004-14 में 28 हजार करोड़ था, जबकि मोदी सरकार में 2014-24 में बढ़कर 80 हजार करोड़ करने का काम किया गया। शाह ने कहा कि पूरे संसार में सबसे अच्छा कोविड प्रबंधन भारत में हुआ है। पूरा विश्व आज इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहा है। कोविड आते ही हमने वैक्सीन बनाने की शुरूआत की।

मप्र के मुख्यमंत्री के नवाचारों से बेहतर हुआ प्रदेश वासियों का जीवन : प्रधानमंत्री

भोपाल, (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के किए गए नवाचारों से प्रदेश वासियों का जीवन बेहतर हुआ है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉ. यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, यही कामना है कि ईश्वर उन्हें दीर्घ और स्वस्थ जीवन प्रदान करें और वे जन सेवा में इसी प्रकार निरंतर सक्रिय रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का मंगलवार को अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री के अलावा केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों और संगठन पदाधिकारियों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार विकास और सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। उन्होंने बाबा महाकाल से मुख्यमंत्री डॉ. यादव के उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की मंगलकामना की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने बधाई संदेश में कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास और उन्नति के नव शिखर को स्पर्श करे, यही कामना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित केंद्रीय मंत्रीगण का आभार माना।

इनके अलावा मुख्यमंत्री डॉ. यादव को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री ने बधाई दी। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा, भाजपा के संगठन मंत्री हितानंद शर्मा सहित कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों और संगठन पदाधिकारी ने जन्म दिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के जन्मदिवस पर मुख्यमंत्री निवास पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा एवं राजेंद्र शुक्ल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, विश्वास सारंग, एंदल सिंह कंषाना, इंदर सिंह परमार, राकेश शुक्ला, कृष्णा गौर, धर्मेंद्र सिंह लोधी, विधायकगण, मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, जनसंपर्क आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े सहित वरिष्ठ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं, सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने पुष्प-गुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा, मिष्ठान वितरण और वाद्ययंत्रों के माध्यम से अपनी प्रसन्नता और उत्साह का प्रकटीकरण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को गदा और कृपाण भी भेंट की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को कार्यकर्ताओं ने विशाल पुष्पहार पहनाकर जन्मदिन की बधाई दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिन की शुरूआत मुख्यमंत्री निवास स्थित मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना कर की। उन्होंने निवास स्थित गौशाला में सर्व सुखदायिनी गौ माता की सेवा कर प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए प्रार्थना की तथा विकसित मध्य प्रदेश के सभी संकल्प पूर्ण करने के लिए गौ माता से आशीर्वाद प्राप्त किया।

इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गांधीनगर स्थित महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम पहुंच कर कुष्ठ रोगियों पर पुष्प वर्षा के साथ अभिवादन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कुष्ठ रोगियों को भोजन परोसा तथा फल, खाद्य सामग्री, वस्त्र और दैनिक उपयोग की सामग्री भेंट की। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक रामेश्वर शर्मा, वरिष्ठ प्रतिनिधि राहुल कोठारी,समाज सेवी तथा कुष्ठ रोगियों के परिजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आश्रम में उपस्थित मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार नागरिकों के हर प्रकार के कष्ट में साथ खड़ी है। ऐसे लोगों के बीच आकर एक प्रकार से आत्मीय सुख प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर रखते हुए आगे लेकर जाना है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में बड़ा निवेश मिला है और सरकार ने संभागीय स्तर पर औद्योगिक इकाइयों के भूमि-पूजन की शुरूआत कर दी है। पहले भिंड, मुरैना और ग्वालियर में 18 औद्योगिक इकाइयों के भूमि-पूजन किया।

देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) से शिष्टाचार भेंट की।

जल जीवन मिशन के तहत देश के 80 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जलापूर्ति : केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री

नई दिल्ली, (हि.स.)। ग्रामीण परिवारों के लिए नल के पानी तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में इसकी शुरूआत में केवल 3.23 करोड़ (16.71 फीसद) ग्रामीण परिवारों के पास नल के पानी के कनेक्शन थे। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले आंकड़ों के मुताबिक 20 मार्च 2025 तक लगभग 12.30 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को इस योजना के तहत नल के पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। इस प्रकार 20 मार्च, 2025 तक देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.53 करोड़ (80.22 फीसद) परिवारों में नल से जल आपूर्ति की जा रही है।

उक्त जानकारी मंगलवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने दी। इसमें बताया गया कि केंद्र सरकार जल आपूर्ति, जल वितरण, अपशिष्ट जल और ठोस अपशिष्ट उपचार, सीवरेज प्रणाली, उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, जल प्रबंधन और ऊर्जा अनुकूलन के विशिष्ट क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय साझेदारी बना रही है। भारत और डेनमार्क ने 28 सितंबर, 2020 को एक हरित रणनीतिक साझेदारी की है। इसके बाद राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली और डेनिश पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, पर्यावरण मंत्रालय, डेनमार्क (डीईपीए) के बीच सभी ग्रामीण घरों को पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार के उद्देश्य का समर्थन करने के लिए संयुक्त कार्य योजना (2021-2024) तैयार की गई है। कार्य योजना का उद्देश्य जल आपूर्ति, जल वितरण, अपशिष्ट जल उपचार, सीवरेज प्रणाली, उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, जल प्रबंधन और जल क्षेत्र में ऊर्जा अनुकूलन के विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है।

जवाब में जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने बताया कि आज तक 11 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हर घर जल वाले बन गए हैं यानि वहां शत प्रतिशत घरों में नल के पानी की आपूर्ति हो रही है और शेष राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के विभिन्न चरणों में हैं। जल जीवन मिशन के तहत मौजूदा दिशानिदेर्शों के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएसः 10500 मानकों को पाइप जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे पानी की गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क के रूप में अपनाया जाता है।

केंद्र ने नक्सल विरोधी सिविक एक्शन प्रोग्राम के लिए सीएपीएफ को 196 करोड़ रुपये जारी किए : गृह राज्य मंत्री

नई दिल्ली, (हि.स.)। स्थानीय आबादी को वामपंथी उग्रवादियों (एलडब्ल्यूई) के प्रभाव से दूर रखने के लिए केंद्र सरकार ने सिविक एक्शन प्रोग्राम को लागू करने के लिए 2014-15 से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को 196.23 करोड़ रुपये जारी किए हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। केंद्र सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक भारत से नक्सलियों को खत्म करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि वामपंथी उग्रवादियों (एलडब्ल्यूई) के प्रभाव से स्थानीय लोगों को दूर रखने के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) द्वारा नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए चिकित्सा शिविरों और कौशल विकास जैसे विभिन्न नागरिक कार्यकलापों का आयोजन किया जा रहा है। 2014-15 से सीएपीएफ को 196.23 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि सरकार ने नक्सल समस्या से निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने बताया कि सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए, वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों के लिए 2 विशिष्ट योजनाओं अर्थात् सड़क आवश्यकता योजना (आरआरपी) और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) के अंतर्गत 17,589 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गई है। इसमें से 14,618 किलोमीटर का निर्माण हो चुका है।

राय ने बताया कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क में सुधार के लिए 10,505 मोबाइल टावर लगाने की योजना बनाई गई है, जिनमें से 7,768 टावर चालू हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि कौशल विकास के लिए 48 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और 61 कौशल विकास केन्द्र (एसडीसी) स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 46 आईटीआई और 49 एसडीसी कार्यरत हैं। जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 255 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 178 ईएमआरएस कार्यरत हैं। इसके अलावा वित्तीय समावेशन के लिए डाक विभाग ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में बैंकिंग सेवाओं के साथ 5731 डाकघर खोले हैं। 1007 बैंक शाखाएं और 937 एटीएम खोले गए हैं और सबसे अधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 37,850 बैंकिंग संवाददाता (बीसी) चालू किए गए हैं। विकास को और गति देने के लिए, विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) के अंतर्गत, वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करने के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है। 2017 में योजना की शुरूआत के बाद से अब तक 3,563 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

राय ने बताया कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट योजनाओं के अलावा, गृह मंत्रालय वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भारत सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के इष्टतम कार्यान्वयन के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ निकट समन्वय में काम करता है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को अब तक 21,15,936 स्वामित्व विलेख वितरित किए गए हैं। इनमें 20,15,337 व्यक्तिगत और 1,00,599 सामुदायिक हैं।

उन्होंने बताया कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के जनजातीय युवाओं तक पहुंचने के लिए जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम (टीवाईईपी) आयोजित किए जा रहे हैं। टीवाईईपी के माध्यम से आदिवासी युवाओं को देश के अन्य भागों में विकास गतिविधियों और तकनीकी व औद्योगिक उन्नति से अवगत कराया जाता है और उन्हें देश के अन्य भागों के लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव विकसित करने और उन्हें आकांक्षी बनाने में सक्षम बनाया जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य वामपंथी उग्रवादियों के झूठे प्रचार का मुकाबला करना भी है। 2014-15 से अब तक 32500 युवाओं ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया है।

उन्होंने बताया कि नीति के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हिंसा में लगातार कमी आई है और भौगोलिक विस्तार सीमित हुआ है। उन्होंने बताया कि वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की घटनाएं और इसके परिणामस्वरूप नागरिकों और सुरक्षा बलों की मृत्यु 2010 के उच्च स्तर से 2024 में क्रमशः 81 प्रतिशत और 85 प्रतिशत कम हुई हैं।

धीरेंद्र ब्रह्मचारी की संपत्ति अपने कब्जे में लेगी हरियाणा सरकार, लाएगी विधेयक

चंडीगढ़, (हि.स.)। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 'योग गुरु' रहे स्वर्गीय धीरेंद्र ब्रह्मचारी की अरबों रुपये की संपत्ति को अब हरियाणा सरकार अधिग्रहण करेगी। हरियाणा सरकार इस संपत्ति का अधिग्रहण करने, प्रबंधन तथा संचालन के लिए विधानसभा के इसी बजट सत्र में एक विधेयक लेकर आएगी। विधानसभा में बुधवार से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण के लिए मंगलवार को जारी एजेंडे के अनुसार हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर की ओर से विधानसभा में अपर्णा संस्था (प्रबंधन तथा नियंत्रण ग्रहण) विधेयक 2025 पेश किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने अपर्णा संस्था (प्रबंधन तथा नियंत्रण ग्रहण) विधेयक 2025 के माध्यम से आशंका जाहिर की है कि इस प्रॉपर्टी को या तो खुर्दबुर्द किया जा सकता है या फिर इस पर अवैध कब्जा हो जाएगा। इससे योग गुरु धीरेंद्र ब्रह्मचारी का यौगिक क्रियाओं के प्रचार प्रसार के मिशन को गहरी ठेस लगेगी। इसलिए राज्य सरकार ने कानून के माध्यम से इस प्रॉपर्टी को अधिग्रहीत कर उसका प्रबंधन, संचालन और नियंत्रण करने का निर्णय लिया है, ताकि यौगिक क्रियाओं को सुचारू रूप से गति प्रदान की जा सके। वैसे भी हाई कोर्ट का मानना है कि धीरेंद्र ब्रह्मचारी ने चूंकि संन्यास ले लिया था, इसलिए उनकी छोड़ी गई पूरी संपत्ति राज्य को जानी थी। हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर सरकार इस कानून के तहत संपत्ति को अधिग्रहित करने की जानकारी अदालत में देगी। दरअसल, अपर्णा नामक संस्था के नाम यह संपत्ति हरियाणा के गुरुग्राम जिले के गांव सिलोखरा में है, जहां योग आश्रम, चिकित्सालय और यौगिक अध्ययन केंद्र चल रहे हैं।

लखनऊ। जियामऊ स्थित विश्व संवाद केन्द्र में प्रेसवार्ता को संबोधित करते अवध प्रान्त के प्रान्त संघचालक सरदार स्वर्ण सिंह व प्रान्त प्रचार प्रमुख डा.अशोक दुबे।

महंगाई पर लगाम के लिए सरकार ने मांगी गेहूं स्टॉक की स्थिति

नई दिल्ली, (हि.स.)। केन्द्र सरकार ने विक्रेताओं से एक अप्रैल से हर शुक्रवार को गेहूं के स्टॉक की स्थिति घोषित करने को कहा है। समग्र खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन और अफवाहों पर रोक लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारी, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेता और प्रसंस्करणकर्ता को 1 अप्रैल 2025 और उसके बाद अगले आदेश तक हर शुक्रवार पोर्टल पर गेहूं की अपनी स्टॉक स्थिति घोषित करनी होगी।

इसमें कहा गया है कि सभी संबंधित कानूनी संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि पोर्टल पर स्टॉक का नियमित और सही तरीके से खुलासा किया जाए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी श्रेणियों की संस्थाओं के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है।

इसके बाद संस्थाओं को पोर्टल पर गेहूं के स्टॉक का खुलासा करना होगा। कोई भी संस्था जो पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, वह खुद को पंजीकृत कर सकती है और हर शुक्रवार को गेहूं के स्टॉक का खुलासा करना शुरू कर सकती है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग अटकलबाजियों को रोकने, कीमतों को नियंत्रित करने और देश में आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं की स्टॉक स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है।

Page-04_Layout 1 3/25/2025 11:33 PM Page 1

सम्पादकीय

बांग्लादेश से सख्ती से पेश आये भारत

पिछले साल अगस्त में भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहाँ रहने वाले हिन्दुओं के विरुध्द लगातार अत्याचार की घटनायें हो रहीं हैं। वहाँ सैकड़ों हिन्दुओं की हत्या कर दी गई है ।महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है और उनकी संपत्तियाँ लूटी जारही हैं । बांग्लादेश में हिन्दुओं के विरुध्द हो रहे अमानवीय व्यवहार के विरोध में आरएसएस ने भी चिंता जताई है। संघ ने भारत सरकार से वहाँ के हालात पर नजर रखने और हिन्दुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की माँग की है ।

भारत के कड़े रुख को देखते हुए अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस भारत के साथ चर्चा कार संबंधों को मजबूत करने की कवायद में जुटे हैं। परंतु यह कटु सत्य है कि वहां हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों की बदहाल स्थिति बनी हुई है। भारत द्वारा आलोचना के बावजूद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों की अराजक, हिंसक और अमानवीय गतिविधियों पर अंकुश लगाने में असफल ही सिद्ध हुई है। तख्तापलट के बाद बनी अंतरिम सरकार का कट्टरपंथियों के दबाव में कार्य करना इन तथ्यों से पुख्ता होता है कि वह अब तक लोकतंत्र की बहाली में विफल रही है, वह हिंदुओं के विरुद्ध कार्य करने वाली अराजक शक्तियों को कुचलने में नाकाम रही है, और शांतिपूर्ण कानून व्यवस्था की पुनर्स्थापना भी नहीं कर पाई है। इस संदर्भ में भारत को अब महज आश्वासन से संतुष्ट नहीं होना है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच से बांग्लादेश की भारत विरोधी करतूतों का खुलकर विरोध करना चाहिए। निःसंदेह भारत-बांग्लादेश रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे और यदि बांग्लादेश का यही रवैया बना रहा तो आगे हालात और बिगड़ेंगे। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि भारत की जरूरत बांग्लादेश को अधिक है, इसलिए भारत को अपनी मांगों की पूर्ति होने तक तथा अपनी चिंता का स्थायी समाधान होने तक बांग्लादेश पर दबाव बनाए रखना चाहिए। भारत की सदाशयता को उसकी कमजोरी समझने वाले बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने भारत से संबंधों और भाईचारे की भावना में जो जहर घोला है, उसकी भरपाई मुश्किल है। बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत को चरमपंथी मानसिकता से ग्रस्त बांग्लादेश के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो भारत को उसी तरह से बांग्लादेश में सैनिक हस्तक्षेप करना चाहिए जैसा की उसने 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए पाकिस्तान के विरुद्ध किया था।

सिजेरियन डिलीवरी पर नहीं, इसके बिजनेस मॉडल पर सवाल है

प्रियंका सौरभ

क्या आपको मालूम है कि सिजेरियन डिलीवरी या सी-सेक्शन दुनिया में सबसे अधिक की जाने वाली सर्जरी है। सिजेरियन सेक्शन बनाम नार्मल डिलीवरी का विषय काफी चर्चा में रहता है, खासकर तब जब इसका जरूरत से ज्यादा उपयोग होने लगे। कुछ लोग इसे एक बिजनेस मॉडल के रूप में देखते हैं तो कुछ इसे मेडिकल साइंस की उपलब्धि मानते हैं। यह एक सर्जिकल प्रक्रिया है। यह तब की जाती है जब सामान्य (नार्मल) डिलीवरी संभव न हो या मां और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए जोखिम हो। सिर्फ ऐसा हो तो कोई सवाल ही नहीं उठाएगा। मगर आजकल कई बार जरूरत न होने पर भी सिजेरियन डिलीवरी कराई जाती है। निजी अस्पतालों में तो इसे जल्दी और सुविधाजनक समाधान के रूप में देखा जाता है। सिजेरियन अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन जब यह व्यावसायिक फायदे के लिए या बिना ठोस मेडिकल वजह के किया जाता है, तब यह चिंता का विषय बन जाता है। सही जागरुकता और जिम्मेदारी से इसका उपयोग होना चाहिए। पिछले कुछ सालों में भारत सहित कई देशों में सिजेरियन डिलीवरी की दर तेजी से बढ़ी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, केवल 10-15 फीसद मामलों में ही सिजेरियन आवश्यक होता है, लेकिन कई देशों में यह दर 50 फीसद या उससे अधिक हो चुकी है। भारत में कई निजी अस्पतालों में यह दर 50 से 80 प्रतिशत तक देखी गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के निजी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी की दर 40-50 फीसद तक पाई गई, जबकि सरकारी अस्पतालों में यह लगभग 20-25 फीसद थी। स्वास्थ्य बीमा योजना और जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जैसी योजनाओं में बिना आवश्यकता के मरीजों की सर्जरी कर दी जाती है, क्योंकि ऐसी योजनाओं में या तो प्रोत्साहन राशि मिलती है, या फिर बीमा कंपनी को लाभ होता है। इनमें सिजेरियन, हार्निया, गॉलब्लेडर, अपेंडिक्स आदि से सम्बंधित मामले अधिक हैं। यह दुखद है, क्योंकि ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा शोषण गर्भवती महिलाओं का होता है। सिजेरियन डिलीवरी का खर्च सामान्य डिलीवरी से 2-5 गुना अधिक होता है, जिससे अस्पतालों को अधिक मुनाफा होता है। नार्मल डिलीवरी में घंटों का समय लग सकता है, जबकि सीजेरियन एक तय समय में पूरा किया जा सकता है, जिससे अस्पतालों और डॉक्टरों को कम समय में अधिक संख्या डिलीवरी कराने का मौका मिलता है। कुछ डॉक्टर निजी अस्पतालों में अपनी सुविधा के अनुसार डिलीवरी शेड्यूल करना पसंद करते हैं। कुछ महिलाओं को लेबर पेन का इतना डर होता है कि वे खुद सिजेरियन करवाने के लिए तैयार हो जाती हैं। कई बार मरीजों को डराकर यह बताया जाता है कि बच्चा खतरे में है, जिससे वे सिजेरियन के लिए मजबूर हो जाती हैं। यह नैतिक रूप से गलत है। कई प्राइवेट अस्पताल तो अधिक मुनाफे चक्कर में सिजेरियन को ही प्राथमिकता देते हैं। जागरुकता की कमी के चलते कई महिलाएं दर्द से बचने के लिए सिजेरियन का विकल्प चुन लेती हैं, जबकि नार्मल डिलीवरी अधिक लाभदायक होती है। महिलाओं को इस बारे जागरूक किया जाए, ताकि वे नार्मल डिलीवरी को प्राथमिकता दें। डॉक्टर्स को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही सिजेरियन करना चाहिए। प्राकृतिक तरीकों को बढ़ावा दिया जाए, जैसे गर्भावस्था के दौरान योग और सही डाइट ताकि नार्मल डिलीवरी आसान हो सके।

इन सबके साथ-साथ सरकार को सख्ती से नियम लागू करने चाहिए, ताकि अनावश्यक सिजेरियन कम हों। गर्भावस्था के दौरान योग, सही खान-पान और व्यायाम पर ध्यान देना चाहिए। अस्पतालों में सिजेरियन और नार्मल डिलीवरी की दरें सार्वजनिक की जानी चाहिए। महिलाओं को सिजेरियन की सिफारिश मिलने पर दूसरे डॉक्टर से सलाह लेने की आदत डालनी चाहिए। सरकार को निजी अस्पतालों में अनावश्यक सिजेरियन रोकने के लिए सख्त नियम बनाने चाहिए। अस्पतालों को नार्मल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। सिजेरियन डिलीवरी के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए तेलंगाना के एक जिले ने तीन मिनट की एक लघु फिल्म बनाई गई है, 'सीजेरियन ला कू कथेरेधम' (आइए सिजेरियन डिलीवरी को कम करें)। सिजेरियन डिलीवरी तभी सही है जब यह मां और बच्चे की सुरक्षा के लिए जरूरी हो। अनावश्यक सर्जरी से बचना चाहिए, क्योंकि यह शारीरिक और मानसिक रूप से मां के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। (लेखिका, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

आरएनआई नं. DELHIN/2009/28518 स्वामी, सम्पादक, मुद्रक, प्रकाशक रमाकांत पाण्डेय द्वारा दिव्य भारत प्रकाशन के लिए न-93 डी नारायण नगर दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफल इंफोटेक लि., प्रेस, सी-9 सेक्टर 3 नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : रमाकांत पाण्डेय, कार्यकारी सम्पादक : आलोक पाण्डेय, फोन : 7701825882, 7905152597, पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत समाचारों के चयन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी।
E-mail : newdibyabharat@gmail.com

भारत का पानी पर बड़ा संदेश

मुकुंद

इसी महीने 22 मार्च को मनाए गए विश्व जल दिवस पर भारत ने पूरी दृढ़ता के साथ दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। हरियाणा के पंचकूला में 'जल शक्ति अभियानः कैच द रेन-2025' की शुरूआत करते हुए केंद्रीय जल शक्तिमंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि अगर कभी पानी को लेकर तीसरा विश्व युद्ध लड़ा गया तो भारत उसका हिस्सा नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जल सुरक्षित भविष्य का निर्माण किया जा रहा है। पाटिल की यह टिप्पणी बेहद अहम है। इसकी वजह यह है कि दुनिया का 70 फीसदी हिस्सा पानी से तो घिरा है, लेकिन उसमें से पीने योग्य पानी लगभग तीन फीसदी है। 97 फीसदी पानी ऐसा है जो पीने योग्य ही नहीं है। सिर्फ तीन फीसदी पानी पर पूरी दुनिया जीवित है। जल संसाधन मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में एक वर्ष में उपयोग किए जाने वाले जल की शुद्ध मात्रा अनुमानित 1,121 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है। वर्ष 2025 में पीने के पानी की मांग 1,093 बीसीएम तक पहुंच सकती है। 2050 तक यह 1,447 बीसीएम हो सकती है।

इस परिदृश्य के बीच जल शक्तिमंत्री की यह आश्वस्ति यह संकेत देती है कि भारत जल संकट से पार पाने के भरपूर इंतजाम कर रहा है। वैसे भी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर जल संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। मानव सभ्यता में जल की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए वह भावी पीढ़ियों के लिए इस अमूल्य संसाधन की सुरक्षा के लिए सामूहिक कार्रवाई का देशवासियों से आह्वान कर चुके हैं। यह कहने में कोई परहेज नहीं है कि देशवासी उनके आह्वान को गर्व के साथ लेते हैं। वह चाहे गंगा की सफाई का आह्वान हो या स्वच्छता अभियान। साल 2014 के बाद दोनों में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। इस साल जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 'जल शक्ति अभियानः कैच द रेन- 2025' शुरू किया है। इसमें देश के 148 जिलों को जोड़ा गया है, क्योंकि यहां जल संकट की आशंका जताई जा रही थी। जल संचय, जन भागीदारीः जन जागरूकता की ओर थीम वाले इस अभियान में जलवायु परिवर्तन और बढ़ती जल चुनौतियों के मद्देनजर जल सुरक्षा, वर्षा जल संचयन और भू-जल पुनर्भरण के महत्व पर जोर दिया गया है। इस आयोजन के दौरान ही वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से जल-जंगल-जनः एक प्राकृतिक बंधन अभियान भी शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जंगलों, नदियों और झरनों के बीच पारिस्थितिक संबंधों को बहाल करना है। जल शक्तिमंत्री पाटिल ने कहा कि भारत के जल क्षेत्र में परिवर्तनकारी प्रगति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। आज पूरे देश में नागरिकों के दरवाजों तक पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा है। उन्होंने दोहराया कि सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है और प्रत्येक नागरिक के योगदान से ही वास्तविक अर्थ में जल सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है।

पाटिल ने कहा कि जहां भी बारिश हो उसे इकट्ठा कर वहीं रिचार्ज करना होगा।

पंचकूला में जल शक्ति अभियान और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें शामिल हैं-वर्षा जल संचयन प्रणाली, बोरवेल रिचार्ज परियोजना, सूक्ष्म सिंचाई पहल, तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, गोबरधन परियोजना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शेड प्रमुख हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज जल संरक्षण के लिए समावेशी और रणनीतिक दृष्टिकोण की नींव रखी गई है।सरकार ने हर बूंद अनमोल (हर बूंद मायने रखती है) के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।

मगर विश्व जल दिवस पर व्यक्त की गई कुछ आशंकाओं पर भी गौर करना होगा। मसलन जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री मोदी को खुला पत्र लिखकर भारत से ग्लेशियरों के संरक्षण में नेतृत्व करने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ग्लेशियरों को बचाने के कदम नहीं उठाए गए, तो अगले महाकुंभ तक नदियां सूखकर रेत में बदल सकती हैं। वांगचुक हाल ही में अमेरिका की यात्रा से लौटे हैं। वांगचुक ने लद्दाख में एक ग्लेशियर से बर्फ का एक टुकड़ा लेकर अपनी यात्रा शुरू की थी। ताकि जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से पिघलते ग्लेशियरों की समस्या की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया जा सके। वांगचुक ने पत्र में लिखा है कि भारत को ग्लेशियरों के संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि हिमालय पृथ्वी पर आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाद बर्फ और बर्फीले पानी का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है और इसे तीसरे ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां भी इन ग्लेशियरों से निकलती हैं। वांगचुक प्रधानमंत्री मोदी की 'मिशन लाइफ' योजना की सराहना करते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे प्रमुख ग्लेशियरों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाना चाहिए और उनके संरक्षण के लिए खास नीतियां बनानी चाहिए।

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

उत्कर्ष के आठ वर्ष योगी सरकार

डॉ. सौरभ मालवीय

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने द्वितीय कार्यकाल के तीन वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। उन्होंने 25 मार्च 2022 को द्वितीय बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस अवसर पर उन्होंने शपथ लेते हुए कहा था कि मैं आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।

योगी आदित्यनाथ अपनी इस शपथ का किस प्रकार हृदय से पालन कर रहे हैं, यह सर्वविदित है। इससे पूर्व उन्होंने प्रथम बार 17 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वह पांच बार गोरखपुर से सांसद रहे चुके हैं। प्रदेश की जनता को उनकी कार्यशैली इतनी सर्वोत्तम लगी कि उसने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में पुनः भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से विजयी बना दिया अर्थात 403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 273 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। इस प्रकार योगी आदित्यनाथ को द्वितीय बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में लगभग साढ़े तीन दशक के पश्चात किसी राज्नीतिक दल को पुनः सत्ता में लाने वाले योगी आदित्यनाथ प्रथम राजनेता हैं। उन्हें अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में अनेक समस्याओं से जूझना पड़ा। उन पर अनेक आरोप लगे। उन पर बुल्डोजर से लोगों के मकान तोड़ने के आरोप लगे। इसके लिए उनकी बहुत आलोचना हुई, परंतु उन्होंने इसकी कोई चिंता नहीं की तथा अपना कार्य को निरंतर जारी रखा। उनके शासनकाल में प्रदेश में धार्मिक गतिविधियों को अत्यंत प्रोत्साहित किया जा रहा है। महाकुंभ का सफल आयोजन इस बात का प्रमाण है। महाकुंभ से पूर्व प्रयागराज के ऐतिहासिक मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण किया गया। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पर्यटन विभाग, स्मार्ट सिटी एवं प्रयागराज विकास प्राधिकरण मिलकर यह कार्य संपन्न किया। मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आस्था एवं सुविधा को प्राथमिकता दी। महाकुंभ मेले के दृष्टिगत प्रदेश को हरभरा बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अतिरिक्त स्वच्छता पर विशेष बल दिया गया। यातायात सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया। योगी आदित्यनाथ के परिश्रम का परिणाम है कि इस मेले में 50 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान कर पुण्य अर्जित किया। इसके अतिरिक्त राज्य में प्रत्येक वर्ष कांवड़ यात्रा पर यात्रियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। यात्रियों के मार्ग में टेंट लगाए जाते हैं। उन पर हेलिकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाती है। प्रशासनिक अधिकारी इस आयोजन में बढ़ चढ़कर सम्मिलित होते हैं।

वास्तव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना किसी पूर्वाग्रह एवं भेदभाव के कार्य करते हैं, जिससे लोगों में सरकार के प्रति सकारात्मक संदेश जाता है। उनकी समयावधि में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकरों को उतरवा दिया गया। रमजान से पूर्व मस्जिदों की निरीक्षण किया गया कि उनमें लाउडस्पीकर तो नहीं लगे हैं। इस वर्ष होली पर मस्जिदों को तिरपाल से ढक गया।

वास्तव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के चाल, चरित्र एवं चेहरे के अनुसार ही हिंदुत्व की छवि को सुदृढ़ करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। प्राचीन नगरों के नाम परिवर्तित करना तथा अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर का निर्माण इसके उदाहरण हैं। सरकार नमामि गंगे योजना के अंतर्गत गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल करने पर विशेष बल दे रही है। गंगा का प्रदूषण कम करने के लिए स्मार्ट गंगा सिटी परियोजना पर कार्य चल रहा है। योगी सरकार राज्य में पर्यटन विशेषकर धार्मिक पर्यटन को भी प्रोत्साहित कर रही है। राज्य में गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना प्रारम्भ की गई है, जिसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में निरा श्रय लोगों को आवास देने के लिए उत्तर प्रदेश आवास विकास योजना प्रारम्भ की गई। निर्धन परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आरम्भ की गई। प्रवासी श्रमिकों को आजीविका देने के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान प्रारम्भ किया गया। बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आरम्भ की गई। बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन तथा मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई। राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना प्रारम्भ की गई। बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता नामक योजना आरम्भ की गई। राज्य के श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ देने के लिए श्रमिक पंजीकरण योजना प्रारम्भ की गई। श्रमिकों के भरण पोषण के लिए राज्य में श्रमिक भरण पोषण योजना आरम्भ की गई है। इसके साथ ही राज्य की समृद्धि के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए परम्परागत खेती विकास योजना चलाई जा रही है। खेतों को पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश निःशुल्क बोरिंग योजना तथा उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना संचालित की जा रही है। इनके अंतर्गत लड़कियों के विवाह के लिए सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के विवाह लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

योगी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य कर रही है। प्रदेश में विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्रों एवं उनके नये भवनों की स्थापना की जा रही है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण किय जा रहा है। उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। उच्च शिक्षा में 119 राजकीय महाविद्यालयों में ई-लर्निंग

अतिरिक्त बीज ग्राम योजना के अंतर्गत किसानों को धान एवं गेहूं के बीज पर विशेष अनुदान दिया जा रहा है। पारदर्शी किसान सेवा योजना के अंतर्गत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को समुचित उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है। किसानों को ऋण के बोझ से मुक्त करने के लिए किसान ऋण मोचन योजना प्रारम्भ की गई। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

प्रदेश में अनाथ बच्चों को शरण देने के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारम्भ की गई। महिला सशक्तिकरण के लिए भी सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों की पुत्रियों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत पुत्री की शिक्षा और विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त लोगों को घर बैठे बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बैंकिंग संवाददाता सखी योजना प्रारम्भ की गई है। इससे जहां लोगों को घर पर बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, वहीं महिलाओं को भी रोजगार प्राप्त हुआ है।

प्रदेश में अनेक पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना तथा उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पेंशन योजना सम्मिलित हैं। सरकार लड़कियों और दिव्यांगों के विवाह के लिए अनुदान प्रदान कर रही है। उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं तथा 87 राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं की व्यवस्था की गई है तथा प्रदेश के 27 विश्वविद्यालयों द्वारा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ 111 अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 26 नये सरकारी पॉलिटेक्निक स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 24 निमार्णाधीन हैं।

सरकार ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले और विभिन्न विभागों में 24 पदों की पहचान करने वाले खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी बनाने का भी निर्णय लिया है। एक जिला एक खेल योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी योगी सरकार सरहनीय कार्य कर रही है। प्रदेश के सभी 4600 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हेल्थ एटीएम लगाए जा रहे हैं। प्रदेश के 65 जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय चल रहे हैं तथा गोरखपुर और रायबरेली में एम्स चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त आयुष्मान कार्ड के माध्यम से प्रदेश के करोड़ों लोगों को पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत लाया गया है। योगी सरकार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर है। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेफ सिटी योजना प्रारम्भ की गई है। विद्युत क्षेत्र में भी योगी सरकार उत्कृष्ट कार्य किया है। परिवहन के क्षेत्र में भी सरकार ने सराहनीय कार्य किए हैं।

निःसंदेह उत्तर प्रदेश में योगी श्री आदित्य नाथ ने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के पश्चात प्रदेश प्रदेश में विकास कार्यों की गंगा बहा दी है। आज उत्तर प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में देशभर में अपनी पृथक पहचान स्थापित की है। कृषि उत्पादों में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है। गन्ना एवं चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश लगातार देश में प्रथम स्थान पर रहा। गन्ना मूल्य का भुगतान कर उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी रहा। खाद्यान्न गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आंवला एवं दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम रहा। तिलहन उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। किसानों को देय अनुदान को डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। उत्तर प्रदेश किसानों के लिए बाजार को व्यापक बनाने हेतु मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का प्रथम राज्य है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में भी उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा।

लोगों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम रहा। इसी प्रकार उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी रहा। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत लोगों को लाभान्वित कर देश में द्वितीय स्थान पर रहा।

निर्माण कार्यों में भी उत्तर प्रदेश किसी से पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 40 लाख से अधिक निर्माण एवं निर्माण कार्यों को स्वीकृति देकर उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पांच एक्सप्रेस वे का एक साथ निर्माण कर अग्रणी रहा। साथ ही 30 नये मेडिकल कॉलेजों का निर्माण करके भी उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है। उत्तर प्रदेश आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के आधार कार्ड सीडिंग, आवास चयन, प्रथम द्वितीय, तृतीय किस्त जारी करने और आवास निर्माण आदि के प्रदर्शन में भी अग्रणी रहा। उत्तर प्रदेश दो करोड़ 61 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण करके भी देश में प्रथम स्थान पर रहा है।

उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक कोरोना जांच एवं टीकाकरण करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश कोरोना काल में सर्वाधिक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित करने वाला राज्य रहा। उत्तर प्रदेश कोरोना काल में दूसरे राज्यों से घर वापस आने वाले कामगारों तथा असंगठित श्रमिकों, फेरी वालों, रिक्शा चालकों, कुलियों, पल्लेदारों आदि को निःशुल्क खाद्यान्न एवं भरण पोषण भत्ता देने वाला अग्रणी राज्य है। नोएडा में उत्तर भारत के प्रथम डेटा सेंटर की स्थापना हुई।

औद्योगीकरण के लिए भूमि उपलब्धता एवं आवंटन में भी उत्तर प्रदेश देश के शीर्ष राज्यों में सम्मिलित है। साथ ही उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना में देश में अग्रणी रहा। सैनिटाइजर और मास्क उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सरकारी नौकरियां और रोजगार देने वाला राज्य है।

उत्तर प्रदेश ने एक जनपद-एक योजना को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उत्तर प्रदेश सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करने वाला उत्तर भारत का प्रथम राज्य है। उत्तर प्रदेश ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 101 करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित कर डेढ़ करोड़ श्रमिकों को रोजगार दिया। उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य है।

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक सात करोड़ दो लाख खाते खोले गए। उत्तर प्रदेश अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 36 लाख 60 हजार 615 लोगों को लाभान्वित कर देश में अग्रणी रहा। उत्तर प्रदेश ई-मार्केट प्लेस जेम के माध्यम से सर्वाधिक सरकारी खरीददारी करने में अग्रणी रहा। उत्तर प्रदेश ई-चालान व्यवस्था लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। ई-प्रोसिसक्यूशन प्रणाली लागू करने में भी यह राज्य अग्रणी है। उत्तर प्रदेश ने 39 करोड़ 42 लाख पौधारोपण करके रिकॉर्ड स्थापित किया। उत्तर प्रदेश मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला प्रथम राज्य है। उत्तर प्रदेश सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं पारदर्शिता में भी अग्रणी है।

उत्कृष्ट कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश को देश में सर्वाधिक प्रदर्शन का पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को दो करोड़ रुपये का कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश को पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ई-टेंडरिंग प्रणाली में उत्तर प्रदेश ने सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए अवार्ड प्राप्त किया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी बसों में पैनिक बटन एवं सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य बना। उत्तर प्रदेश में अविरल और निर्मल गंगा के प्रति जन जागरूकता के लिए प्रथम बार गंगा यात्रा का आयोजन किया गया। अयोध्या दीपोत्सव में उत्तर प्रदेश ने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। भाजपा अपने घोषणा-पत्र में जनता से किए वादों को पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

(लेखक- लखनऊ विवि में प्राध्यापक है।)

Page-05_Layout 1 3/26/2025 3:51 AM Page 1

मुख्य चुनाव अधिकारी ने राष्ट्रीय, केंद्र शासित प्रदेश के राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की।

मुख्य न्यायाधीश ने जीएमसीएच जम्मू, श्रीनगर में कानूनी सहायता क्लिनिक और सहायता केंद्रों के कामकाज को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई

दिव्य भारत संवाददाता

जम्मू। न्यायमूर्ति ताशी रबस्तान, मुख्य न्यायाधीश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख (संरक्षक-इन-चीफ, जेएंडके लीगल सर्विसेज अथॉरिटी) के सम्मानित मार्गदर्शन में जेएंडके लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने आज जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) के सभी सचिवों, सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसीएच) जम्मू और श्रीनगर के चिकित्सा अधीक्षकों और जेल अधीक्षकों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की जेलों के चिकित्सा अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक बुलाई। इसका उद्देश्य पूरे क्षेत्र में सुधारात्मक सुविधाओं में कैदियों को उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल के लिए कानूनी सहायता तंत्र की व्यापक समीक्षा करना और उसे सुदृढ़ करना था।

विचार-विमर्श के दौरान, जीएमसीएच जम्मू और श्रीनगर में हाल ही में उद्घाटन किए गए कानूनी सहायता क्लीनिकों पर विशेष जोर दिया गया यह संकल्प लिया गया कि इन कानूनी सहायता क्लीनिकों को नामित कानूनी सहायता रक्षा परामर्शदाताओं (एलएडीसी) और अर्ध-कानूनी स्वयंसेवकों (पीएलवी) के साथ पूरी तरह से चालू किया जाना चाहिए ताकि कैदियों के लिए कानूनी सहायता तक निर्बाध और समय पर पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

पहुंच और पहुंच को बढ़ाने के लिए, यह आगे अनिवार्य किया गया कि पीएलवी, कानूनी सहायता परामर्शदाता और जीएमसीएच जम्मू और श्रीनगर द्वारा नामित नोडल अधिकारियों के संपर्क विवरण सभी जेलों में प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक कैदी अपने अधिकारों से अवगत हो और प्रक्रियात्मक बाधा के बिना कानूनी सहायता मांग सके। यह पहल विशेष चिकित्सा ध्यान में तेजी लाने और लंबित कानूनी मामलों के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करने के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, जेल अधीक्षकों को जीएमसीएच जम्मू और श्रीनगर में उपलब्ध कानूनी सहायता क्लीनिकों से विशेष चिकित्सा उपचार प्रदान करने के सभी लाभों का लाभ उठाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया गया, जिसमें विशेष चिकित्सा देखभाल, मनोवैज्ञानिक परामर्श और कैदियों के लिए कानूनी परामर्श शामिल हैं मुख्य न्यायाधीश ने कैदियों की समग्र भलाई सुनिश्चित करने के लिए जेल अधिकारियों, कानूनी सेवा संस्थानों और स्वास्थ्य पेशेवरों को शामिल करते हुए समन्वित दृष्टिकोण के महत्व को दोहराया।

बैठक का समापन सभी हितधारकों की ओर से सुधार संस्थानों में कानूनी सहायता के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ हुआ, साथ ही कानूनी सहायता क्लीनिकों, कानूनी साक्षरता पहलों और पुनर्वास कार्यक्रमों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जेल कैदियों की स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए। जम्मू-कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण न्याय को बनाए रखने, कानूनी उपायों तक पहुंच सुनिश्चित करने और सभी व्यक्तियों, विशेष रूप से हिरासत में लिए गए लोगों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करने के अपने मिशन में दृढ़ है।

उपायुक्त पुंछ ने आगामी धार्मिक आयोजनों की तैयारियों की समीक्षा की

दिव्य भारत संवाददाता

पुंछ। उपायुक्त विकास कुंडल ने आगामी धार्मिक आयोजनों जैसे शब-ए-कद्र, नवरात्र, ईद-उल-फितर और बैसाखी की तैयारियों की समीक्षा के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और धार्मिक नेताओं की एक बैठक बुलाई।

बैठक में धार्मिक प्रमुखों और प्रमुख नागरिकों के लिए प्रत्येक दिन की आवश्यक आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया गया। चर्चा में स्वच्छता उपायों में वृद्धि, निर्बाध बिजली आपूर्ति, विश्वसनीय पेयजल पहुंच, सुरक्षा प्रावधान, यातायात प्रबंधन, राशन आपूर्ति का पर्याप्त स्टॉक, खाद्य वस्तुओं की कीमतों और गुणवत्ता की निगरानी के साथ-साथ चिकित्सा सुविधाएं और पार्किंग व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक के दौरान संबोधित की गई विशेष चिंताओं में नवरात्र उत्सव के दौरान मंदिर परिसरों में सुरक्षा, स्थानीय बाजारों की सजावट, ईद पर दूरदराज के क्षेत्रों में पर्याप्त राशन का प्रावधान और खालसा सिरजना दिवस पर 11 अप्रैल को निर्धारित नगर कीर्तन के दौरान आवश्यक चिकित्सा सहायता शामिल थी। डिप्टी कमिश्नर ने समुदाय के नेताओं द्वारा उठाई गई नई मांगों को संबोधित करते हुए सभी अधिकारियों से पिछली प्रथाओं का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने त्यौहार के मौसम के दौरान खाद्य कीमतों और गुणवत्ता की निगरानी के महत्व पर जोर दिया और बिजली विकास विभाग (पीडीडी) और सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) विभाग को पर्याप्त बिजली और पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, सीएएंडएफसीएस विभाग को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया कि आवश्यक वस्तुएं आसानी से उपलब्ध रहें। नगर समिति को आवश्यक प्रकाश व्यवस्था के साथ-साथ पूजा स्थलों और सार्वजनिक समारोहों के आसपास स्वच्छता मानकों को बनाए रखने का निर्देश दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने व्यापक सुरक्षा उपायों का आश्वासन दिया और जिले में स्पष्ट सांप्रदायिक सद्भाव की सराहना की। बैठक के अंत में, डिप्टी कमिश्नर ने घनिष्ठ अंतर-विभागीय सहयोग का आह्वान किया और सुचारू त्यौहार समारोह सुनिश्चित करने के लिए समय पर व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सहायक आयुक्त राजस्व, सहायक आयुक्त विकास, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तहसीलदार हवेली, जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य पशुपालन अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, एक्सईएन जल शक्ति, एक्सईएन जेपीडीसीएल, ईओ नगर पालिका और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि, कानूनी माप विज्ञान अधिकारी और धार्मिक नेताओं और प्रमुख सामुदायिक सदस्यों ने भाग लिया।

3.6 लाख से अधिक छात्र जेके बोस की परीक्षा में शामिल हुए

जम्मू। जेके बोस ने 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित कीं, जो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में 3600 केंद्रों पर आयोजित की गईं। कुल मिलाकर, 3.6 लाख से अधिक छात्रों ने सॉफ्ट और हार्ड दोनों क्षेत्रों में स्थापित निर्धारित केंद्रों पर परीक्षा दी। जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सभी जिलों में निष्पक्ष, सुचारू और पारदर्शी परीक्षा आयोजित करने में अपना पूरा सहयोग देने के लिए स्कूल शिक्षा, पुलिस, जिला प्रशासन और डाक विभागों के प्रति आभार व्यक्त किया है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने आउटरीच कार्यक्रम एससीईआरटी जम्मू ऑन व्हील्स शुरू किया

दिव्य भारत संवाददाता

जम्मू। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), जम्मू और कश्मीर ने एक महत्वाकांक्षी आउटरीच कार्यक्रम, एससीईआरटी जम्मू ऑन व्हील्स शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य जम्मू संभाग में शिक्षक शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को मजबूत करना है, जिसे अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा और एससीईआरटी जम्मू और कश्मीर के निदेशक शांतमनु ने हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम में एससीईआरटी जम्मू की संयुक्त निदेशक प्रोफेसर सिंधु कपूर और डाइट जम्मू की प्रिंसिपल अंजलि गुप्ता भी मौजूद थीं। यह अनूठा कार्यक्रम शिक्षक शिक्षकों को आधुनिक शैक्षणिक उपकरण, नवीन शिक्षण पद्धतियां और जमीनी स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शोध-आधारित सर्वोत्तम अभ्यास प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रासंगिक रूप से, एससीईआरटी जम्मू ऑन व्हील्स एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य शिक्षक शिक्षा संस्थानों में अंतराल को पाटना और शैक्षिक सुधारों का प्रभावी प्रसार सुनिश्चित करना है। इस आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से, एससीईआरटी जम्मू, डीआईईटी जम्मू और डीआईईटी कुड के साथ मिलकर एक अधिक सूचित, कुशल और अभिनव शिक्षण समुदाय बनाने का प्रयास करता है, जो अंततः छात्रों और बड़े पैमाने पर शिक्षा प्रणाली को लाभान्वित करता है। फ्लैग-ऑफ समारोह में बोलते हुए, शांतमनु ने निरंतर शिक्षक प्रशिक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, एससीईआरटी जम्मू ऑन व्हील्स जमीनी स्तर पर शिक्षकों के लिए पेशेवर विकास को अधिक सुलभ और प्रभावशाली बनाने की दिशा में एक अग्रणी कदम है। यह आउटरीच जम्मू संभाग में सहयोग, ज्ञान-साझाकरण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगा। एससीईआरटी जम्मू की संयुक्त निदेशक प्रोफेसर सिंधु कपूर ने शिक्षा में नीति और व्यवहार के बीच की खाई को पाटने में एससीईआरटी जम्मू ऑन व्हील्स के महत्व और भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एससीईआरटी जम्मू संभाग के तहत विभिन्न डीआईईटी में पहलों के अभिसरण को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के अभिविन्यास कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षक शिक्षकों को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। डाइट कुड, जीएचएसएस टिकरी, जीएमएस लेहनु और जीजीएमएस डोगरा तथा उधमपुर जिले के 11 जोनों के शिक्षक प्रशिक्षकों के ओरिएंटेशन सत्रों में प्रमुख शैक्षिक पहलों पर चर्चा की गई। इनमें निपुण भारत (एफएलएन), पीएम ई-विद्या, दीक्षा, निष्ठा, मूल्यांकन प्रकोष्ठ बहुभाषी प्रकोष्ठ, एनईपी प्रकोष्ठ और समावेशी शिक्षा शामिल हैं। एससीईआरटी जम्मू के संकाय सदस्यों ने सीखने की प्रक्रिया को समृद्ध करने के लिए संवादात्मक चर्चाओं और अनुभव साझा करने वाले सत्रों का नेतृत्व किया। पूरे कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम समन्वयक राकेश कुमार चोबर ने किया। डाइट कुड के प्रधानाचार्य ने इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया तथा शिक्षक प्रशिक्षकों के पेशेवर विकास पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, इस तरह के आउटरीच कार्यक्रम हमें अपनी शिक्षण पद्धतियों को आधुनिक शैक्षिक प्रथाओं के साथ जोड़ने में मदद करेंगे।

मुख्य चुनाव अधिकारी ने राष्ट्रीय, केंद्र शासित प्रदेश के राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की

दिव्य भारत संवाददाता

जम्मू। भारत के चुनाव आयोग) के निदेशों के अनुसार, मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ), जम्मू और कश्मीर, पदुरंग के पोले ने आज निर्वाचन भवन, रेल हेड, जम्मू में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और केंद्र शासित प्रदेश के राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और महासचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई।बैठक का प्राथमिक उद्देश्य एक सहयोगात्मक संवाद को बढ़ावा देना और सभी हितधारकों के बीच चुनावी प्रक्रियाओं की व्यापक समझ सुनिश्चित करना था। बातचीत के दौरान, चुनावी ढांचे के प्रमुख पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। इनमें चुनावी प्रक्रिया का कानूनी ढांचा; चुनावों को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधानों पर व्यापक स्पष्टीकरण, स्थापित दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करना, पंजीकरण प्रक्रिया; मतदाता पंजीकरण प्रक्रियाओं की गहन व्याख्या, सटीकता और पहुंच पर जोर चुनाव प्रणाली की दक्षता, पारदर्शिता और समावेशिता बढ़ाने और बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) और बूथ स्तर के एजेंटों (बीएलए) की भूमिका के लिए ईसीआई द्वारा लागू किए गए नवीनतम सुधारों पर प्रकाश डाला; मतदाता सुविधा और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता में बीएलओ और बीएलए की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। बैठक में अतिरिक्त सीईओ राहुल शर्मा, नोडल अधिकारी काजी अलहतर, डिप्टी डीईओ जम्मू रामेश्वर कुमार और सीईओ कार्यालय में अवर सचिव हुमा खान भी शामिल हुए। सीईओ ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के प्रति ईसीआई की प्रतिबद्धता दोहराई।

उपायुक्त राजौरी ने शब-ए-कद्र, जमात-उल-विदा और ईद-उल-फितर के लिए प्रबंधों की समीक्षा की

दिव्य भारत संवाददाता

राजौरी। डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा ने आज डीसी कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले में शब-ए-कद्र, जमात-उल-विदा और ईद-उल-फितर के प्रबंधों को अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

डीसी ने निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए निर्देश जारी किए और संबंधित अधिकारियों को शहर में उचित सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। स्ट्रीट लाइटों के कामकाज की भी समीक्षा की गई, जिसमें किसी भी तरह की खराबी को तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए गए।

निर्बाध जलापूर्ति के महत्व पर जोर देते हुए डीसी ने पीएचई विभाग को सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में राशन के वितरण का भी जायजा लिया और समय पर वितरण पर जोर दिया। समारोह के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और यातायात नियमों पर गहन चर्चा की गई। कार्यक्रमों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्थानों पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की भी समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को भीड़भाड़ से बचने के लिए पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था करने का निर्देश दिया। बाजार जांच टीमों को मटन, चिकन, पनीर, फल और सब्जियों सहित आवश्यक वस्तुओं की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण पर कड़ी निगरानी रखने, अधिक कीमत वसूलने से रोकने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद को स्वच्छता और सफाई बनाए रखने के लिए कचरे का वैज्ञानिक निपटान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में एडीसी राजीव खजूरिया; एसीआर मोहम्मद जहांगीर खान; अतिरिक्त एसपी बिक्रम कुमार; पूर्व इंजीनियर पीडीडी अब्दुल रशीद; एडी एफसीएस एंड सीए रोहित; ईओ नगर परिषद यूसुफ उल उमर; प्रशासक औकाफ कयूम मीर; सीएमओ डॉ मनोहर राणा; बीओपीरमंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता और अन्य जिला और क्षेत्रीय अधिकारी शामिल हुए।

हमें अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं, लोक कलाओं, पारंपरिक शिल्प और प्राचीन ज्ञान प्रणाली को संरक्षित करने के लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए एलजी।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने आउटरीच कार्यक्रम एससीईआरटी जम्मू ऑन व्हील्स शुरू किया।

प्राचीन ज्ञान का प्रसार करने के लिए पीढ़ियों को एक साथ लाना चाहिए : उपराज्यपाल

दिव्य भारत संवाददाता

जम्मू। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने आज श्री कैलाख ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट द्वारा बाबा जित्तो ऑडिटोरियम, एसकेयूएएसटी जम्मू में आयोजित जम्मू-कश्मीर सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज भी उपस्थित थे। अपने संबोधन में, उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिक मूल्यों और भाषाई विरासत को बढ़ावा देने और प्रचार करने के लिए श्री कैलख ज्योतिष और वैदिक संस्थान और ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों के प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि अधिक सामंजस्यपूर्ण और प्रबुद्ध समाज को बढ़ावा देने के लिए संगठनों और व्यक्तियों को भारत के कालातीत ज्ञान और मूल्य प्रणालियों को संरक्षित और फैलाने के लिए आगे आना चाहिए। हमारी प्राचीन सभ्यता ने अपने समृद्ध सांस्कृतिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक योगदान के माध्यम से मानवता को गहराई से प्रभावित किया और वसुधैव कुटुम्बकम के विचार को आकार दिया। हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित, संरक्षित और बढ़ावा देने और अपनी सभ्यता के प्राचीन ज्ञान का प्रसार करने के लिए पीढ़ियों को एक साथ लाना चाहिए।

उपराज्यपाल ने कहा, यह भी जरूरी है कि हम ऐसे विभिन्न तरीके विकसित करें जिनसे समाज में विरासत के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके। उपराज्यपाल ने युवाओं, धार्मिक संगठनों और नागरिक समाज के सदस्यों से प्राकृतिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत और जीवंत विरासत के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने को कहा।

उन्होंने आगे कहा कि सतत विकास को प्राथमिकता देने के अलावा, हमें अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं, लोक कलाओं, पारंपरिक शिल्प और प्राचीन ज्ञान प्रणाली को संरक्षित करने के लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उपराज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत के विजन को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों, कलाकारों और अध्यात्मवादियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा, हमारी विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सभी हितधारकों को शामिल करते हुए समन्वित प्रयास महत्वपूर्ण हैं।

उपराज्यपाल ने आगे हर वर्ग, खासकर युवा पीढ़ी से सतत जीवन शैली के ब्रांड एंबेसडर बनने और धरती माता के प्रति हमारे कर्तव्यों के बारे में समाज में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया गया, एक वृत्तचित्र फिल्म का प्रदर्शन किया गया और माननीय उपराज्यपाल के जीवन पर महंत रोहित शास्त्री द्वारा संपादित 'अभिनंदन ग्रंथ' नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। जम्मू-कश्मीर सांस्कृतिक महोत्सव का उद्देश्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक परंपराओं और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना था। महोत्सव के दौरान स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजनों और लोक नृत्यों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। सशस्त्र बलों की ताकत और तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करने और युवाओं को सेना में शामिल होने और राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करने के लिए एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इस अवसर पर एसकेयूएएसटी-जम्मू के कुलपति प्रोफेसर बी.एन. त्रिपाठी, विधान सभा सदस्य श्री शाम लाल शर्मा, समाज कल्याण आयुक्त सचिव श्री संजीव वर्मा, श्री कैलख ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रोहित शास्त्री, वरिष्ठ अधिकारी, धार्मिक प्रमुख और बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।

Page-06_Layout 1 3/26/2025 1:32 AM Page 1

उत्तरी इजरायल में एक सुरक्षाकर्मी हमले वाली जगह पर गश्त करते हुए, यहां एक हमलावर ने अचानक हमला कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी जबकि एक सुरक्षाकर्मी को घायल कर दिया।

फिलिस्तीन समर्थक कोलंबिया विवि की छात्रा ने ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा किया

वाशिंगटन, (हि.स.)। फिलिस्तीन समर्थक एक छात्रा ने सोमवार को ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा किया है। आरोप लगाया गया है कि अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन विभाग ने उसे फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के बाद निष्कासित करने के लिए हिरासत में लेने का प्रयास किया। यह सब राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से हुआ। मांग की गई है कि 'फिलिस्तीनी अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े व्यक्तियों को आव्रजन प्रवर्तन के लिए लक्षित करने के पैटर्न और अभ्यास' पर रोक लगाई जाए।

न्यूज चैनल सीएनएन की खबर में मुकदमे में दर्ज विवरण के आधार पर यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि 21 वर्षीय युनसेओ चुंग अमेरिका की स्थायी निवासी है। वह अमेरिका में लंबे समय से रह रही हैं। वह सात साल की थी जब उसका परिवार दक्षिण कोरिया से अमेरिका आया था। वह न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय की जूनियर छात्रा है। वह कोलंबिया अंडर ग्रेजुएट लॉ रिव्यू में भी शामिल रही है। कानूनी क्षेत्र में इंटर्नशिप की है।

चुंग के वकीलों का तर्क है कि उनका मुवक्किल गैर-नागरिकों की कतार में से एक है, जिसमें महमूद खलील और रंजनी श्रीनिवासन शामिल हैं, जिन्हें ट्रंप प्रशासन फिलिस्तीनी अधिकारों के समर्थन में बोलने के लिए दंडित कर रहा है। यह कार्रवाई राज्य विभाग और होमलैंड सुरक्षा विभाग की अपनाई गई नीति के माध्यम से की जा रही है। मुकदमे में कहा गया है कि चुंग ने हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध के खिलाफ कैंपस में विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। उन्हें विश्वविद्यालय की इमारतों पर पोस्टर लगाने के लिए अनुशासनात्मक प्रक्रिया का सामना करना पड़ा।

वकीलों के अनुसार, 5 मार्च को चुंग ने कोलंबिया विश्वविद्यालय प्रशासन की दी गई अत्यधिक सजा के विरोध में विद्यार्थियों के धरने में भाग लिया। इस दौरान उसे न्यूयॉर्क पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुकदमे में कहा गया है कि विश्वविद्यालय ने गिरफ्तारी के कारण चुंग के परिसर में आने-जाने पर रोक लगा दी। संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी ने 10 मार्च को चुंग के वकील को बताया कि उसकी वैध स्थायी निवासी स्थिति को रद्द किया जा रहा है।मुकदमे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, विदेश मंत्री मार्को रुबियो, अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी, होमलैंड सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोएम साथ ही आईसीई के कार्यवाहक निदेशक टॉड एम. लियोन्स और न्यूयॉर्क आसीई के कार्यवाहक फील्ड ऑफिस निदेशक विलियम पी. जॉयस को प्रतिवादी बनाया गया है। होमलैंड सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि चुंग को आव्रजन कानूनों के तहत निष्कासन कार्यवाही के लिए बुलाया जा रहा है। चुंग का आचरण चिंताजनक है। चुंग को आव्रजन न्यायाधीश के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

न्यूजीलैंड में 6.8 तीव्रता का भूकंप, नागरिकों को समुद्र तट से दूर रहने की चेतावनी

वेलिंगटन, (हि.स.)। न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के निचले हिस्से में लोगों ने भूकंप के शक्तिशाली झटके महसूस किए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.8 मापी गई। न्यूजीलैंड की आपदा एजेंसी यह आकलन कर रही है कि इससे सुनामी का कोई खतरा है या नहीं। न्यूजीलैंड भूकंप के लिहाज से अत्यधिक सक्रिय 'रिंग ऑफ फायर' पर बसा है। रिंग ऑफ फायर लगभग 40,000 किलोमीटर का घेरा है। यह प्रशांत महासागर के अधिकांश हिस्से को घेरने वाले ज्वालामुखियों और समुद्री खाइयों से भरा है। द न्यूजीलैंड हेराल्ड अखबार के अनुसार, 6.8 तीव्रता का भूकंप जटिल भूकंपीय वातावरण में आया है। ऑस्ट्रेलियाई टेक्टोनिक प्लेट सीमा के पास सबसे तेज कंपन हुआ। ऑस्ट्रेलियाई प्लेट प्रशांत प्लेट के नीचे गोता लगाती है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में इस क्षेत्र में कई मंजिल ऊंची सुनामी लहरें उठने के बारे में चेतावनी दी थी। यह भूकंप 2:43 बजे आया। इसका केंद्र द्वीप के उत्तर-पश्चिम में लगभग 160 किलोमीटर दूर धरती से 33 किलोमीटर की गहराई पर रहा। नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने साउथलैंड और फियोर्डलैंड क्षेत्रों के लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह दी है। एजेंसी का कहना है कि समुद्र की असामान्य धाराएं खतरा बन सकती हैं। न्यूजीलैंड की सरकारी भूकंप निगरानीकर्ता जियोनेट ने कहा कि 4700 से अधिक लोगों ने भूकंप का झटका महसूस किया। भूकंप विज्ञानी डॉ. फिन इल्स्ले-केम्प के विक्टोरिया विश्वविद्यालय के सहकर्मी इस क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को भूकंप के लिहाज से कम आंका गया है। यहां अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम शोध किया गया है। जबकि यहां शक्तिशाली भूकंप आए हैं। 2009 का 7.8 तीव्रता वाला फियोर्डलैंड भूकंप खाई के उत्तरी छोर के करीब आया था। इससे 1945 में नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में 25,000 गुना अधिक ऊर्जा उत्सर्जित हुई थी। इसकी क्षमता दक्षिण द्वीप को मोड़ने के लिए पर्याप्त थी। इल्सले-केम्प ने कहा कि विशेषज्ञ भूकंप के फोकल मैकेनिज्म पर ध्यान केंद्रित करेंगे। साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार इतिहास का सबसे शक्तिशाली भूकंप करीब 3800 साल पहले 9.5 मैग्नीट्यूड के साथ उत्तरी चिली में आया। इसके झटके चिली से करीब 5,000 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड तक महसूस किए गए और सुनामी आ गई थी। इस शोध के सह लेखक प्रोफेसर जेम्स गोफ के अनुसार अभी तक माना जा रहा था कि उत्तर में इस तरह की घटना नहीं हो सकती, लेकिन अब हमारे पास इससे जुड़े सबूत हैं। उत्तरी चिली के अटाकामा रेगिस्तान तट को दुनिया का सबसे शुष्क वातावरण वाला क्षेत्र माना जाता है। इसके बावजूद शोधकर्ताओं को यहां तट से सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक समुद्री जीवों और तलछट के सबूत मिले हैं, जो किसी बड़ी सुनामी के जरिए पहुंचे होंगे। इस स्टडी में समुद्र तट के करीब खुदाई में कई इमारतें मिली हैं जो किसी ताकतवर लहर से तबाह हुई हैं। सुनामी के बाद इस जगह को बसने में करीब 1000 साल लग गए। प्रोफेसर जेम्स गोफ का कहना है कि दक्षिणी गोलार्ध में यह सबसे पुराना उदारण है, जहां भूकंप और सुनामी की वजह से लोगों की जिंदगी पर इतना गहरा असर पड़ा। प्रोफेसर गोफ के अनुसार, इस अध्ययन की शुरूआत से पहले संयोग से न्यूजीलैंड के चैथम द्वीप पर एक साइट की जांच की गई। वहां कई बड़े पत्थर मिले, जो करीब 3800 साल पुराने थे। यह वही वक्त था जब उत्तरी चिली में भूकंप और सुनामी आई थी।

उत्तर कोरिया ने दी दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान को चेतावनी

प्योंगयांग, (हि.स.)। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के हाल ही में किए गए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की निंदा की है। उत्तर कोरिया ने कहा कि यह शत्रुतापूर्ण है। वह किसी भी उकसावे का निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार है। उत्तर कोरिया की सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) ने मंगलवार को यह प्रतिक्रिया दी। केसीएनए ने कहा कि पिछले सप्ताह सोमवार से गुरुवार तक दक्षिण कोरिया के दक्षिणी रिसॉर्ट द्वीप जेजू के अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में किए गए त्रिपक्षीय संयुक्त समुद्री अभ्यास से तनाव का खतरा बढ़ गया है। यह अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप की जनवरी में दूसरी बार वापसी के बाद इस साल अपनी तरह का पहला सैन्य अभ्यास है।

बेलग्रेड में नेटो की बमबारी में ध्वस्त हुए सेना मुख्यालय को अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद को लीज पर देने का विरोध करते हुए छात्र।

ओली सरकार के एक निर्णय से नेपाल में राजनीतिक भूचाल, सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी दल तक सड़कों पर उतरे

काठमांडू, (हि.स.)। नेपाल सरकार के एक निर्णय के कारण नेपाल की राजनीति में भूचाल आ गया है। सोमवार देर रात हुए निर्णय का सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं ने ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी कड़ा विरोध किया है। इस समय काठमांडू की सड़कों पर सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।

सोमवार की देर रात को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक कुलमान घीसिंग को पद से बर्खास्त करने का निर्णय किया है। बीती रात को जैसे ही यह खबर बाहर आई तत्काल सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस के महामंत्री सहित कई बड़े नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया।

नेपाली कांग्रेस के दोनों महामंत्री गगन थापा और विश्वप्रकाश शर्मा ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। इन दोनों ही नेताओं ने कहा कि सरकार का यह फैसला गैर जरूरी है और इससे सरकार को कोई फायदा नहीं होने वाला है। थापा और शर्मा ने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रधानमंत्री के इस फैसले में हमारी पार्टी का कोई समर्थन नहीं है।

सत्ता पक्ष के अन्य बड़े नेता शेखर कोइराला, अर्जुन नरसिंह केसी, एनपी साउद सहित कई नेताओं ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। इन नेताओं ने सरकार की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री पर असफल होने का आरोप लगाया। सभी नेताओं ने एमाले के साथ गठबंधन पर पुनर्विचार करने की भी मांग की। सत्ता पक्ष के अलावा सभी विपक्षी दल के नेताओं ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेन और जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने बयान जारी करते हुए ओली सरकार पर एक अच्छे प्रशासक को बर्खास्त करने का आरोप लगाया है।

आज काठमांडू की सड़कों पर विपक्षी दल के साथ साथ कुछ सत्ता पक्ष के संगठनों द्वारा सुबह से ही ऊर्जा मंत्री और प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ स्थानों पर प्रधानमंत्री के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। माओवादी के नेतृत्व में रहे समाजवादी मोर्चा की तरफ से काठमांडू में सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है।

बलूचिस्तान में राज्य विरोधी गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारी नपेंगे

इस्लामाबाद, (हि.स.)। पाकिस्तान के सर्वाधिक अशांत प्रांत बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने राज्य विरोधी गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने सभी आयुक्तों और जिला अधिकारियों को ऐसे कर्मचारियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। उन्होंने सोमवार को बलूचिस्तान में समग्र कानून और व्यवस्था की स्थिति पर एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों का यह आचरण अस्वीकार्य है। पाकिस्तान के समाचार द न्यूज के अनुसार, बैठक में बलूचिस्तान के मुख्य सचिव शकील कादिर खान, पुलिस महानिरीक्षक मोजाम जाह अंसारी, प्रमुख विभागों के सचिव, सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद, सभी संभागीय आयुक्त, उपायुक्त, डीआईजी और जिला पुलिस अधिकारियों ने एक वीडियो लिंक के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया। बुगती ने कहा कि बलूचिस्तान में कोई भी राजमार्ग बंद नहीं किया जाए। जिलास्तर पर राज्य विरोधी तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा। प्रांत के सभी शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रगान अवश्य बजाया जाना चाहिए और राष्ट्रीय ध्वज अवश्य फहराया जाना चाहिए। इन आदेशों का पालन न करने वाले संस्थानों के प्रमुखों को इस्तीफा देना होगा।

मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जो सरकारी नीतियों के अनुसार काम नहीं कर सकता है, उसे स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए। बलूचिस्तान में किसी भी चौकी पर जबरन वसूली को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में ऑस्कर विजेता फिलिस्तीनी निर्देशक पर हमला

यरुशलम, (हि.स.)। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में ऑस्कर विजेता फिल्म 'नो अदर लैंड' के फिलिस्तीनी सह-निर्देशक हमदान बल्लाल पर हमला हुआ है। आरोप है कि यहां बसे इजराइली समूह ने इनको पीटा और इसके बाद इजराइली सैनिक उन्हें अपने साथ ले गए। अमेरिकी न्यूज चैनल सीएनएन को उनके सहयोगियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने यह जानकारी दी।

इस फिल्म के निर्देशन में सहयोगी बेसल अद्रा के अनुसार, वह सोमवार को हमदान को देखने उनके घर गए थे। वो सुस्या गांव में रहते हैं। उन्होंने परेशानी में बुलाया था। बल्लाल के घर के बाहर इजराइलियों का एक समूह पथराव कर रहा था। इजराइली पुलिस और सेना भी उनके घर के बाहर थी। इजराइली सैनिक उन सभी पर गोलियां चला रहे थे।

सीएनएन की खबर के अनुसार, इजराइली सेना ने कहा कि फिलिस्तीनियों और इजराइलियों के बीच हिंसक टकराव की सूचना पर वहां पहुंचे थे। यह टकराव आतंकवादियों के इजराइली नागरिकों पर पथराव के बाद शुरू हुआ। कुछ आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर भी पत्थर फेंके। इसके बाद तीन फिलिस्तीनी और एक इजराइली नागरिक को पूछताछ के लिए ले जाया गया।

इस फिल्म के एक अन्य सह-निर्देशक और इजराइली मूल के युवल अब्राहम ने कहा कि बल्लाल के सिर और पेट में चोटें आई हैं। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल रहा है। यहूदी अहिंसा केंद्र में रहने वाले पांच अमेरिकी कार्यकर्ताओं ने कहा कि वह घटनास्थल पर मौजूद थे। हम लोगों पर भी इजराइल के निवासियों ने हमला किया। बल्लाल को गिरफ्तार करते उन्होंने नहीं देखा।

उल्लेखनीय है कि 'नो अदर लैंड' फिल्म का निर्माण संयुक्त रूप से इजराइल और फिलिस्तीन के निर्देशकों ने किया है। यह फिल्म वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल करने की कहानी बयां करती है। बल्लाल को इससे पहले भी डराया और धमकाया जा चुका है।

नो अदर लैंड में वेस्ट बैंक के हेब्रोन की पहाड़ियों पर स्थित गांवों में इजराइली अधिकारियों के विध्वंस का दस्तावेजीकरण किया गया है।डॉक्यूमेंट्री में ग्रामीणों को बलपूर्वक बेदखल करने के इजराइली सरकार के प्रयास को फिल्माया गया है।

काराकास में विमान से उतरते हुए विस्थापित, इन्हें अमेरिका से बाहर किये किया गया है।

ट्रंप का फरमान, अगर वेनेजुएला से तेल और गैस खरीदी तो देना होगा 25 फीसदी टैक्स

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वह उन सभी देशों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाएंगे जो वेनेजुएला से तेल और गैस खरीदते हैं। ट्रंप के इस कदम से भारत के एनर्जी सेक्टर को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप ने वेनेजुएला को निशाना बनाने के लिए यह कदम उठाया है लेकिन इसका असर भारत, चीन जैसे देशों पर पड़ेगा क्योंकि ये देश वेनेजुएला से भारी मात्रा में तेल और गैस खरीदते हैं। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक और कूटनीतिक नीतियों को प्रभावित करने के मकसद से सहयोगियों और विरोधियों, दोनों पर टैरिफ लगाए हैं। वेनेजुएला पर टैरिफ लगाने को लेकर उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल नेटवर्क पर लिखा- वेनेजुएला हमारी स्वतंत्रता के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण रहा है। इसलिए, कोई भी देश जो वेनेजुएला से तेल और गैस खरीदता है, उसे अमेरिका के साथ किसी तरह के व्यापार पर 25 फीसदी का टैरिफ देना होगा। ट्रंप ने सोमवार को वेनेजुएला से तेल खरीद पर टैरिफ लगाने के एक आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसके बाद वेनेजुएला से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों तरह की तेल, गैस खरीददारी पर 25 फीसदी का टैरिफ लगेगा। टैरिफ 2 अप्रैल से लागू हो सकता है।

वेनेजुएला का तेल अमेरिका, स्पेन, भारत और ब्लैक मार्केट में आता है। अमेरिका, स्पेन और भारत क्रमशः शेवरॉन कॉर्प, रेप्सोल एसए और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिए गए लाइसेंस के जरिए वेनेजुएला से तेल खरीदते हैं जबकि चीन ब्लैक मार्केट के जरिए वेनेजुएला से तेल खरीदता है। भारत की सरकारी तेल रिफाइनरी कंपनियों ने हाल के महीनों में वेनेजुएला से तेल खरीदना कम कर दिया है। वहीं, रिलायंस ने लगातार वेनेजुएला से तेल खरीदा है और उसे तेल पर भारी छूट भी मिली है। भारत वेनेजुएला के तेल के प्रमुख खरीदारों में से एक है, जिसने 2024 में 2.2 करोड़ बैरल तेल आयात किया है। जनवरी में इसकी खरीद बढ़कर 254,000 बैरल प्रति दिन हो गई, दिसंबर 2023 में, आयात करीब 191,600 बैरल प्रति दिन था जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 127,000 बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा था।

अगर अमेरिका के टैरिफ से तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इससे भारत में महंगाई बढ़ सकती है जिससे परिवहन, मैन्यूफैक्चरिंग और समग्र आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है। दुनिया भर में युद्धों और ट्रंप के आने के बाद से भू-राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है जिससे देखते हुए भारतीय रिफाइनर्स को आने वाले महीनों में व्यापार नीतियों और आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप ने आदेश में कहा है कि टैरिफ तब तक लागू रहेगा जब तक कोई देश कम से कम एक साल के लिए वेनेजुएला के तेल आयात को बंद नहीं कर देता। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्प और भारत पेट्रोलियम कॉर्प वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीद के लिए कम टेंडर जारी कर रही हैं क्योंकि रूसी तेल की आपूर्ति अब स्थिर होने लगी है। रूसी तेल पर लगे पश्चिमी प्रतिबंध ट्रंप के आने के बाद से नरम पड़े हैं और रूसी तेल बिना प्रतिबंध वाले टैंकरों के जरिए भारत पहुंच रहा है।

Page-07_Layout 1 3/26/2025 1:14 AM Page 1

मियामी ओपन टेनिस में डेनिला कोलिंस आर्यिनका सबालेंका के खिलाफ शॉट खेलती हुई।

केरल के पावरलिफ्टर जोबी मैथ्यू की नजरें 51 वर्ष की उम्र में पैरालंपिक स्वर्ण पर

नई दिल्ली, (हि.स.)। खेलों में उम्र सिर्फ एक संख्या होती है, अगर खिलाड़ी शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हो। टाइगर वुड्स (49), क्रिस्टियानो रोनाल्डो (40) और राफेल नडाल (38) जैसे दिग्गज एथलीटों ने उम्र की बाधाओं को पार कर दुनिया में अपने खेल का लोहा मनवाया है। इसी तरह 48 वर्षीय केरल के पैरा पावरलिफ्टर जोबी मैथ्यू भी अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और मेहनत से खेल जगत में छाए हुए हैं।

जन्म से ही विकसित न हो सकी टांगों के बावजूद जोबी ने अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चार स्वर्ण और एक कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। सोमवार को उन्होंने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 65 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। यह पिछली बार की तुलना में एक सुधार है, जब उन्होंने 59 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता था। हालांकि, कोट्टायम में जन्मे इस बहुप्रतिभाशाली पैरा एथलीट ने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और पिछले 25 वर्षों से खेलों में सक्रिय हैं। उनका सपना 2028 लॉस एंजेलेस पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतना है और इसके लिए उनकी उम्र कोई मायने नहीं रखती।

जोबी प्रॉक्सिमल फीमरल फोकल डेफिशिएंसी नामक जन्मजात विकार से ग्रसित हैं, जिसमें जांघ की हड्डी या तो अविकसित होती है या अनुपस्थित होती है, जिससे एक पैर छोटा हो जाता है लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी बनने नहीं दिया। भारत पेट्रोलियम में मैनेजर के रूप में कार्यरत जोबी ने शुरूआत में शॉट पुट और डिस्कस थ्रो में हाथ आजमाया, फिर पावरलिफ्टिंग में कदम रखा। इसके अलावा, वह टेबल टेनिस में भी राष्ट्रीय पदक जीत चुके हैं।

जोबी ने 2022 में कोरिया में आयोजित पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप (एशिया-ओशिनिया वर्ल्ड चैंपियनशिप) में हिस्सा लिया और 59 किग्रा वर्ग में चार अलग-अलग कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीते। इनमें एशियन स्वर्ण पदक (59 किग्रा), ओशिनिया स्वर्ण पदक (59 किग्रा), सर्वश्रेष्ठ लिफ्ट स्वर्ण (59 किग्रा) और कुल लिफ्ट स्वर्ण (59 किग्रा) शामिल है। हालांकि, 2023 में चीन में आयोजित एशियन पैरा गेम्स के लिए क्वालीफाई करने के बावजूद गलत एक्रेडिटेशन कार्ड के कारण उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। यह उनके करियर का सबसे मुश्किल समय था। जोबी के पास पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने का भी मौका था, लेकिन कुछ निजी कारणों से वह इसमें हिस्सा नहीं ले सके। लेकिन अब उनका पूरा ध्यान 2028 लॉस एंजेलेस पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने पर है।

जोबी मैथ्यू का मानना है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स जैसे इवेंट्स अनुभवी पैरा एथलीट्स के लिए बड़ा मंच हैं। उन्होंने कहा, यह टूर्नामेंट आगामी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चयन का एक प्रमुख प्लेटफॉर्म है, जिसे एसएआई द्वारा आयोजित किया जाता है। अन्य प्रतियोगिताएं ज्यादातर निजी संगठनों या नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित की जाती हैं लेकिन खेलो इंडिया पैरा गेम्स में अंपायर, रेफरी और खेल प्रशासन से जुड़े अधिकारी एथलीट्स का गंभीरता से मूल्यांकन करते हैं।

जब उनसे पूछा गया कि क्या 51 साल की उम्र में पैरालंपिक्स में पदक जीत सकते हैं? तो जोबी ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, मेरे लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। मुझे अपने भगवान और अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है। अगर मुझे सही समर्थन मिला तो मैं यह कर सकता हूं। यह सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरे देश के लिए भी है।

अक्टूबर में शुरू होने वाले सीजन 4 के साथ होगी पीवीएल की रोमांचक वापसी

नई दिल्ली, (हि.स.)। प्राइम वॉलीबॉल लीग (पीवीएल) अपने चौथे सीजन के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस सीजन की शुरूआत 2 अक्टूबर को होगी। बेहतरीन सीजन-3 के हाई ऑक्टेन मुकाबलों के बाद चौथा सीजन बड़ा और बेहतर होने जा रहा है। यह पूरे देश में प्रशंसकों को विश्व स्तरीय वॉलीबॉल एक्शन का तोहफ प्रदान करेगा।

पीवीएल सीजन 4 की शुरूआत बहुप्रतीक्षित खिलाड़ियों की नीलामी से होगी। इसका आयोजन 8 जून को कालीकट में होगा, जहां टीम के मालिकों और फ्रेंचाइजियों को प्रतिभाओं के एक रोमांचक पूल से अपनी टीम बनाने और एक और प्रतिस्पर्धी और रोमांचक सीजन के लिए मंच तैयार करने का अवसर मिलेगा।

अपनी जोशीली वॉलीबॉल संस्कृति और खेल के प्रति गहरे प्रेम के लिए जाना जाने वाला कालीकट पीवीएल नीलामी की मेजबानी करने वाला चौथा शहर बन जाएगा। यह देश भर में लीग के बढ़ते प्रभाव को और प्रदर्शित करेगा। नीलामी के लिए खिलाड़ियों का पंजीकरण आधिकारिक तौर पर एक मई को शुरू होगा और इच्छुक एथलीटों के पास पंजीकरण करने के लिए 31 मई तक का समय होगा।

इस तरह उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने और भारत में पेशेवर वॉलीबॉल के उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा। इस संबंध में अधिक जानकारी आने वाले दिनों में साझा की जाएगी।

पीवीएल की वापसी पर बेसलाइन वेंचर्स के प्रबंध निदेशक और सह-संस्थापक तुहिन मिश्रा ने कहा, हम प्राइम वॉलीबॉल लीग को इसके चौथे सीजन के लिए वापस लाने के लिए रोमांचित हैं। पीवीएल ने पिछले कुछ वर्षों में काफी तरक्की की है और पिछले तीन सीजन की सफलता उल्लेखनीय रही है। लीग ने न केवल अपनी रीच का विस्तार किया है, बल्कि भारत में उभरती वॉलीबॉल प्रतिभाओं के लिए एक मजबूत मंच भी प्रदान किया है। हमें उम्मीद है कि पीवीएल सीजन-4 शीर्ष स्तर की प्रतिभा और लगातार बढ़ते प्रशंसक आधार के साथ नई ऊंचाइयों को छुएगा। हमारा लक्ष्य भारत में वॉलीबॉल के खेल को ऊपर उठाना है, खिलाड़ियों को एक बेहतरीन मंच और प्रशंसकों को एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करना है।

प्राइम वॉलीबॉल लीग के सीईओ जॉय भट्टाचार्य ने कहा, पीवीएल ने खुद को भारत की सबसे रोमांचक खेल लीग्स में से एक के रूप में स्थापित किया है। सीजन 4 इसे एक और पायदान ऊपर ले जाने के लिए तैयार है। तथ्य यह है कि हमारे पास सीजन 3 में तीन अलग-अलग चैंपियन हैं, जो प्रतिस्पर्धा की गुणवत्ता और लीग के अप्रत्याशित और जबरदस्त रूप से प्रतिस्पर्धी होने के बारे में बहुत कुछ बताता है। हर टीम खिताब जीतने के असली मौके के साथ सीजन में प्रवेश करेगी। इससे पीवीएल प्रशंसकों के लिए एक रोमांचक उत्सव बन जाता है। नीलामी आने वाली है और खिलाड़ियों के पंजीकरण जल्द ही शुरू हो रहे हैं। हम आगे एक शानदार सीजन के लिए कमर कस रहे हैं। फ्रेंचाइजी, खिलाड़ियों और प्रशंसकों का उत्साह हमारे जुनून को बढ़ाता है, और हम शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकते।

युवाओं के लिए मैत्रीपूर्ण वॉलीबॉल मैच का आयोजन

राजौरी, (हि.स.)। मैत्रीपूर्ण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना खेल भावना, टीम वर्क और नागरिक-सेना संबंधों को बढ़ावा देने के प्रयास में भारतीय सेना ने एक मैत्रीपूर्ण वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय युवाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई जिससे एकता और सहयोग की भावना को बल मिला। इस मैच ने सेना को समुदाय के साथ सकारात्मक और अनौपचारिक माहौल में जुड़ने का अवसर प्रदान किया। इसने प्रतिभागियों के बीच शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जिससे आपसी विश्वास और मित्रता की गहरी भावना को बढ़ावा मिला। भारतीय सेना खेल और सांस्कृतिक जुड़ाव के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

लंदन में विश्वकप फुटबॉल के यूरोपीय क्वालीफायर मुकाबले में भाग लेते हुए खिलाड़ी।

दिल्ली

दिल्ली के विकास और प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा यह बजट : आशीष सूद

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह बजट दिल्ली के विकास और प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ- सबका विकास सिद्धांत पर आधारित वर्ष 2025-26 का यह बजट विकसित दिल्ली- संकल्प पत्र-2025 को धरातल पर लाने की शुरूआत है।

उन्होंने कहा कि मात्र 33 दिन के शासन काल में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हमारी सरकार ने बजट में 1 लाख करोड़ रुपये का सरकारी व्यय का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 31 फीसद अधिक है। इस बजट में दिल्ली के वर्तमान युवा और भावी पीढ़ी का भी विशेष ध्यान रखा गया है। शिक्षा क्षेत्र में सीएश्री स्कूल, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन, राष्ट्रनीति डॉ अब्दुल कलाम लैंग्वेज लैब जैसी नवाचारी योजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं।

गौरतलब है कि वर्ष 2025-26 में हमारी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 19291 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार के वर्ष 2024-25 के बजट से लगभग 18 फीसद अधिक है।

दिल्ली सरकार का बजट स्वागत योग्य, मिलकर करेंगे काम : एनडीएमसी उपाध्यक्ष

नई दिल्ली, (हि.स.)। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के ऐतिहासिक एक लाख करोड़ के बजट का स्वागत किया। उन्होंने इसे राष्ट्रीय राजधानी के समग्र विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने बताया कि बजट बुनियादी ढांचे, जल आपूर्ति, स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, हरित ऊर्जा और सामाजिक सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को मजबूत करेगा।

कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'विकसित भारत' पहल के अनुरूप 'विकसित दिल्ली' के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे राजधानी को एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और वैश्विक शहर में बदलने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये बजट, शहर के विकास में एक मिल का पत्थर साबित होगा। चहल ने कहा कि एनडीएमसी को इस बजट से बहुत फायदा होगा, खासकर स्वच्छता, हरित क्षेत्र विस्तार, जल आपूर्ति में सुधार, सड़कों और बिजली के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के साथ-साथ पर्यटन और सांस्कृतिक प्रचार जैसे क्षेत्रों में।

उन्होंने यह भी कहा कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और ओवरहेड केबलों को खत्म करने के उद्देश्य से 'पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना' के प्रावधानों से बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में काफी सुधार होगा। इसके अलावा, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की पहल से दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों की वैश्विक पहचान बढ़ेगी। चहल ने कहा कि समय पर शिकायत करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा एनडीएमसी 311 पर आधारित एक नए मोबाइल ऐप के विकास के लिए बजट में 15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि 2016 में लॉन्च किया गया एनडीएमसी 311 नागरिक मुद्दों की रिपोर्ट करने के लिए एक डिजिटल गेटवे के रूप में कार्य करता है। 2022 में प्रधान मंत्री से ई-गवर्नेंस अवार्ड 2021 प्राप्त हुआ। अधिकांश शिकायतों का समाधान 24 घंटों के भीतर कर दिया जाता है। ऐप में एक स्वचालित एस्केलेशन प्रणाली भी है, जो कनिष्ठ से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक त्वरित शिकायत समाधान सुनिश्चित करती है।

चहल ने घोषणा की कि एनडीएमसी 311 जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को एकीकृत करेगा। जिससे स्वचालित शिकायत विश्लेषण और वास्तविक समय समाधान सक्षम होंगे।

दिल्ली पुलिस में कई अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर

नई दिल्ली, (हि.स.)। गृह मंत्रालय ने दिल्ली में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंगलवार को दिल्ली सरकार के बजट वाले दिन ही ताबड़तोड़ 28 पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। तबादले में आईपीएस व दानिक्स अधिकारी भी हैं। कुछ अधिकारियों की पदोन्नति भी हुई है।

गृह मंत्रालय के उप सचिव कुलविंदर सिंह ने स्थानांतरण सूची जारी की है।

इस सूची के अनुसार यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा। जिन अधिकारियों का तबादला हुआ है उसमें 2001 बैच के आईपीएस बी शंकर जायसवाल, आईपीएस परमादित्य, विक्रमजीत सिंह, पुष्पेंद्र कुमार, नुपूर प्रसाद के साथ ही 2008 बैच के आईएएस शरत कुमार सिन्हा भी हैं।

जानकारी के अनुसार आईपीएस बी शंकर जायसवाल को सेंट्रल रेंज का जॉइंट सीपी बनाया गया है। आईपीएस परमादित्य सेंट्रल रेंज से स्पेशल ब्रांच में जॉइंट सीपी होंगे। सिक्योरिटी जॉइंट सीपी का पदभार संभाल रहे 2006 बैच के आईपीएस पुष्पेंद्र कुमार अब ईस्टर्न रेंज के जॉइंट सीपी होंगे।

नुपूर प्रसाद को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से लाइसेंसिंग का जॉइंट सीपी बनाया गया है। इसी क्रम में आईपीएस विक्रमजीत सिंह को सिक्योरिटी में भेजा गया है।

पलवल के हिंद टर्मिनल से पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को दिखाई गई हरी झंडी

नई दिल्ली, (हि.स.)। देश के माल परिवहन और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नया आयाम देते हुए मंगलवार को पलवल में हिंद टर्मिनल लॉजिस्टिक्स पार्क से पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई और टर्मिनल को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तेज रेलमार्ग से जोड़ दिया गया। यह उद्घाटन उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) के प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय रेल और निजी लॉजिस्टिक भागीदारों के बीच बढ़ रहे सहयोग को रेखांकित करता है।

डीएफसीसीआईएल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस नई कनेक्टिविटी के माध्यम से देश के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) पर माल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रेलवे की देश के माल परिवहन में हिस्सेदारी बढ़ेगी। अब हिंद टर्मिनल्स लॉजिस्टिक्स पार्क पलवल स्थित अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) क्षेत्र के निर्यातकों और आयातकों को प्रतिस्पर्धी डोर-टू-डोर मूल्य निर्धारण प्रदान करने में सक्षम होगा, जो फिलहाल सड़क मार्गों का उपयोग कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न, जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं, औद्योगिक उत्पादों और लघु उद्योग के उत्पादों सहित आवश्यक वस्तुओं की कुशल आवाजाही सुनिश्चित होगी। रेल लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने से उद्योग बढ़ेगा और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों को झंडी दिखाने से पहले प्रवीण कुमार ने न्यू दादरी से न्यू पृथला तक एक व्यापक विंडो-ट्रेलिंग निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने डीएफसी पर माल परिवहन की परिचालन दक्षता और प्रमुख बुनियादी ढांचे की समीक्षा की, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह उच्च मानकों के अनुसार है।

इसके अलावा, प्रवीण कुमार ने डीएफसीसीआईएल के अधिकारियों और प्रमुख हितधारकों के साथ एक व्यापार विकास की बैठक का भी नेतृत्व किया। इस बैठक में इनोवेशन को बढ़ावा देने, माल परिवहन संचालन को सुदृढ़ करने और डीएफसी की ओर अधिक व्यवसाय आकर्षित करने पर गहन चर्चा की गई। डीएफसी कॉरिडोर भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल साबित हो रही है।

डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन रेल माल परिवहन के आधुनिकीकरण में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह भारतीय रेल और डीएफसीसीआईएल की कुशल और सस्टेनेबल लॉजिस्टिक समाधानों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उल्लेखनीय है कि 2,843 किमी लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) नेटवर्क में से, 96 प्रतिशत से अधिक या 2,741 किमी, पहले ही पूरा हो संचालित हो चुका है। 1506 किमी लंबा पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी) उत्तर प्रदेश में नोएडा के नजदीक दादरी से महाराष्ट्र के मुंबई तक फैला है, जो सीमेंट, खाद, कंटेनर, खराब होने वाली वस्तुओं इत्यादि के तेज परिवहन को एक नया आयाम दे रहा है। यह कॉरिडोर लंबी, भारी और डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों के कुशल संचालन के लिए बनाया गया है। डब्ल्यूडीएफसी आज माल परिवहन में क्रांति ला रहा है, देश की माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी को बढ़ा रहा है, लॉजिस्टिक क्षेत्र को सुदृढ़ कर रहा है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रहा है और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है। भारतीय रेल के कुल नेटवर्क का मात्र 4 प्रतिशत होने के बावजूद, डीएफसी 14 प्रतिशत से अधिक माल परिवहन कर रहा है और इसकी क्षमता में लगातार वृद्धि हो रही है।

ड्रग्स तस्करी के मामले में वांछित बदमाश गिरफ्तार

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने ड्रग्स तस्करी के मामले में वांछित शिव शंकर उर्फ गेला को गिरफ्तार किया है।

क्राइम ब्रांच की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि पकड़ा गया शिव शंकर काफी कुख्यात है। इसने हाल ही में एक नाबालिग को भी चाकू मारा था। जांच में पता चला है कि आरोपित दुष्कर्म, हत्या के प्रयास, ड्रग्स तस्करी समेत छह से ज्यादा मामलों में शामिल रहा है।

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में नई दिल्ली के जंतर-मंतर में बढ़ती बेरोजगारी के विरोध प्रदर्शन करते हुए।

Page-08_Layout 1 3/26/2025 3:50 AM Page 1

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मंगलवार को गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित 'बाबा गम्भीरनाथ जी की यौगिक अवदान' विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी में सम्मिलित हुए।

उत्तर प्रदेश की चर्चा आज राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हो रही : स्वतंत्र देव सिंह

प्रयागराज, (हि.स.)। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन को डबल इंजन की सरकार ने सुरक्षा, सुशासन और विकास की जिस यात्रा को प्रारम्भ किया था, वह आज नये भारत के नये उत्तर प्रदेश के रूप में पूरे देश के समक्ष एक मॉडल की तरह प्रस्तुत हुई है। उप्र के ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा आज राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हो रही है। इसके पीछे ट्रिपल सी यानी कल्चर, कनेक्टिविटी एवं कॉमर्स का मंत्र है।

यह बातें मंगलवार को कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जिला पंचायत सभागार में पत्रकारों से कही। सरकार के आठ साल की उपलब्धियों पर उन्होंने कहा कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आम जनों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ ही निवेशकों को कम लागत में अधिक उत्पादन और बेहतर परिणाम की गारंटी देता है। इसी ने उप्र को आर्थिक विकास में ऊंचे पायदान पर पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि वंचित को वरीयता का मूल मंत्र मानकर सरकार ने विगत आठ वर्षों में छह करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। इसी प्रकार पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान मानधन योजना, निःशुल्क सिंचाई, बिचौलियों से आजादी जैसे अनेक कार्यों ने कृषि सेक्टर की तस्वीर बदली है।

मंत्री ने आगे कहा कि जब से भाजपा की सरकार बनी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति रही। जो आज उप्र की कानून व्यवस्था एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत हुई है। महिला सम्बंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उप्र देश में नम्बर एक पर है। उन्होंने कहा कि 2017 तक कुल 14 नगर निगम थे, आज 17 हैं। बीते आठ वर्षों में 125 नये नगरीय निकायों का गठन किया गया है। आज स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सभी नगर निगमों में 10 हजार 300 करोड़ से अधिक की 757 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पहले लोग जात पात देखकर नौकरी देते थे। आज किसी भी धर्म या समुदाय का हो, उसे योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। इसमें किसी का कोई जोर नहीं है। इसके साथ ही लोगों को उद्यम के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 की तुलना में 2024 तक एईएस रोगियों की मृत्यु में 85 प्रतिशत व जेई रोगियों की मृत्यु में 99 प्रतिशत की कमी आई है।

जलशक्ति मंत्री ने कहा कि सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद, श्री देवीपाटन तीर्थ विकास, उप्र ब्रज तीर्थ विकास, श्री विंध्य धाम तीर्थ विकास, श्री चित्रकूट धाम तीर्थ एवं नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद उप्र, श्री शुक्र तीर्थ विकास परिषदों का गठन किया है। उन्होंने बताया कि महाकुम्भ के दौरान पांच नये धार्मिक कॉरिडोर तैयार हुए। जिनमें प्रयागराज-विंध्याचल-काशी, प्रयागराज-अयोध्या-गोरखपुर, प्रयागराज-लखनऊ - नैमिषारण्य, प्रयागराज-राजापुर-चित्रकूट तथा प्रयागराज-मथुरा-वृंदावन एवं शुकतीर्थ गलियारा हैं।

इस अवसर पर विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह, गुरू प्रसाद मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. वीके सिंह, भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, निर्मला पासवान, मण्डलायुक्त विजय विश्वास पंत, जिलाधिकारी रवीन्द्र मॉदड़ सहित तमाम अधिकारी एवं भाजपा के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है : दया शंकर सिंह

धर्मेन्द्र श्रीवास्तव/दिव्य भारत

प्रतापगढ़। प्रदेश सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शहीद उद्यान (कम्पनी गार्डेन) में त्रिदिवसीय विकास उत्सव मेले का आयोजन भव्य रूप से किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ राज्यमंत्री परिवहन विभाग और जिले के प्रभारी दयाशंकर सिंह ने त्रिदिवसीय मेले का फीता काटकर उद्घाटन किया।

प्रभारी मंत्री दया शंकर सिंह,सदर विधायक राजेन्द्र मौर्य,पूर्व मंत्री मोती सिंह और अधिकारियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगायी गयी प्रदर्शनी को देखा। वहीं कार्यक्रम स्थल पर बनाये गये सेल्फी प्वाइन्ट पर सेल्फी भी ली,उसके बाद प्रभारी मंत्री ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष एवं केन्द्र सरकार के 10 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनपद के शहीद उद्यान में त्रिदिवसीय मेले का उत्सव कार्यक्रम भव्य रूप से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पूर्ण कर रहा है। उन्होने कहा कि वर्ष 2017 से प्रदेश में जब से सरकार बनी है तब से हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व

में उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है।

उन्होने कहा कि महिलायें स्वावलम्बी हो रही है, अच्छा पढ़ने वाली बेटियों के लिये स्कूटी उपलब्ध करायी जायेगी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में बेटियों की शादी हेतु 1 लाख रुपए दिया जायेगा। लाभार्थियों के खाते में सीधे योजना की धनराशि भेजी जा रही है। देश के सर्वाधिक निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे है और रोजगार के अवसर बढ़ रहे है।

उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यो की प्रशंसा दुनिया के कई देशों में की जा रही है। प्रयागराज में दिव्य महाकुम्भ का सबसे बड़ा आयोजन किया गया जिसमें 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के माध्यम से युवाओं को बिना किसी ब्याज के ऋण देकर रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार सबके सपने को पूरा कर रही है। उत्तर प्रदेश स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने प्रतापगढ़ में हुये विकास कार्यो के सम्बन्ध में बताया कि 250 करोड़ की लागत से मेडिकल कालेज का निर्माण कराया गया, मनरेगा योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर 2017 व्यक्तिगत खेत तालाब बनाये गये जो विश्व रिकार्ड है,जिले में 11354 करोड़ के 191 एमओयू किया गया जिसके अन्तर्गत 79463 रोजगार सृजित किये गये। जनपद में 26.11 करोड़ की लागत से पुलिस लाईन में ट्रांजिट हास्टल का निर्माण कराया गया, किसान ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत 73123 किसान लाभान्वित हुये, निराश्रित पेंशन योजना के अन्तर्गत 55042 महिलाओं को, वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 154308 वृद्धजनों, दिव्यांगजन पेंशन योजना के अन्तर्गत 22186 दिव्यागजनों को पेंशन दी जा रही है।

सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 5660 गरीब व्यक्तियों की पुत्री का विवाह सम्पन्न कराया गया, कन्या सुमंगला योजना योजना के अन्तर्गत 38260 कन्याएं लाभान्वित हुई, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अन्तर्गत 459117 खाते खुलवाये गये, अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत 121559 व्यक्ति लाभान्वित हुये, आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत 958187 पात्र लाभार्थियों के गोल्डेन कार्ड बनवाये गये, पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत 11501 लोग लाभान्वित हुये, पीएम उज्जवला योजना के तहत 270978 लोग लाभान्वित हुये, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अन्तर्गत 7075 लाभार्थियों को निःशुल्क टूलकिट का वितरण किया गया, 22673 छात्र/छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट एवं 59898 छात्र/छात्राओं को स्मार्ट फोन का वितरण किया गया।

इस अवसर पर विधायक सदर राजेन्द्र कुमार मौर्य ने कहा कि समाज के अन्तिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुचाया जा रहा है। केन्द्र एवं प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास के साथ कार्य कर रही है।

संक्षिप्त समाचार

संभल में कहीं भी नहीं होगा मेले का आयोजन : एएसपी

संभल, (हि.स.)। सैयद सालार मसूद गाजी की याद में मंगलवार को जिले में लगने वाले नेजा मेले के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक श्रीशचंद्र ने मौके का निरीक्षण किया। एएसपी ने बताया कि मेला स्थाना और आसपास किसी भी जगह पर कोई भी आयोजन नहीं किया जा रहा है। लोगों की माने तो इस मेले का आयोजन एक लुटेरे, आक्रांता और हत्यारे की याद में किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज इस दरगाह पर कोई नहीं आया है। सभी लोग इस बात को समझ चुके हैं कि आक्रांता की याद में आयोजित होने वाले किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए। सभी जगह पूरी तरह शांति है और चप्पे-चप्पे पर फोर्स तैनात है। उन्होंने कहा कि किसी को भी सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है और जो कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शादी के 15 दिन बाद ही पति की हत्या कराने वाली दुल्हन को फांसी की मांग

औरैया, (हि.स.)। जिले के फफूंद थाना क्षेत्र में 15 दिन पूर्व शादी कर ससुराल आई दुल्हन ने पति की सुपारी देकर हत्या करवा डाली। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए कातिल पत्नी और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी युवक का परिवार गांव से फरार है। वहीं इस स्तब्ध कर देने वाली घटना ने दूल्हे के घर में मातम पसर गया है। गमगीन परिजन ने कातिल दुल्हन को फांसी देने की मांग की है। सिहापुर निवासी हरिगोविंद ने अपनी सबसे छोटी पुत्री प्रगति की शादी बीते 5 मार्च को मैनपुरी के गांव नगला दीपा निवासी हाइड्रा और क्रेन का कारोबार करने वाले दिलीप यादव से की थी। होली का त्योहार के चलते 10 मार्च को घर के लोग उसकी चौथी लेकर आए। 19 मार्च को दुल्हन प्रगति ने पति के सहार थाना क्षेत्र में घायल हालत में खेतों में होने की सूचना पुलिस और ससुरालीजनों को दी। सैफई में इलाज के बाद दूल्हे दिलीप की मृत्यु हो गई। पहले तो परिजन इसे एक हादसा समझा लेकिन डाक्टरों के सीटी स्कैन में युवक के सिर में गोली फंसी होने की जानकारी से परिजन को शक हुआ। मामले में पुलिस भी सक्रीय हुई तो सभी हैरान रह गए।

जस्टिस वर्मा की इलाहाबाद में नियुक्ति के खिलाफ अधिवक्ता गए हड़ताल पर

प्रयागराज, (हि.स.)। जस्टिस यशवंत वर्मा की इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्ति के खिलाफ मंगलवार को अधिवक्ताओं का गुस्सा उबाल पर आ गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता मंगलवार से हड़ताल पर चले गए, वहीं उन्होंने हाईकोर्ट के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया। अधिवक्ता दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद में स्थानांतरित किए जाने का विरोध कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास में आग बुझाते समय बीते दिनों कथित तौर पर तीन बोरियों में भरे नोट मिले थे। इसके बाद जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की तरफ से एक बैठक हुई थी। कोलेजियम ने जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की संस्तुति की है। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सोमवार को जनरल बॉडी की मीटिंग की थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अपील की गई थी कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद न भेजा जाए। बार एसोसिएशन ने केंद्र सरकार और देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) से जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाए जाने की मांग भी की है।

अब यूपी में खुद को सुरक्षित करता है हर व्यक्ति : मुख्यमंत्री

गोरखपुर, (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत आठ वर्षों में प्रदेश सरकार ने सुरक्षा का बेहतर माहौल दिया तो उसका परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश में हरेक व्यक्ति ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया पैदा किया जबकि आज सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज दिया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया है। नए रोजगार के सृजन किए हैं। एमएसएमई को पुनर्जीवित किया है। इन सबसे उत्तर प्रदेश में निवेश का नया युग आया है। सीएम योगी सेवा, सुरक्षा और सुशासन की आठ वर्ष की प्रदेश सरकार की यात्रा के उपलक्ष्य में गोरखपुर में एक विशेष कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में परिवर्तन की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई ,यह हमारे संकल्प का हिस्सा था। उस संकल्प के तहत हम लोगों ने, भाजपा ने 2017 में जनता जनार्दन के सामने वादा किया था कि सबको सुरक्षा देंगे, सबको सम्मान देंगे। योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर जरूरतमंद को उपलब्ध करवाएंगे। सरकार ने इन सभी वादों को पूरा किया है।

पुलिस से बेखौफ हत्यारों ने होमगार्ड की कर दी हत्या

धर्मेन्द्र श्रीवास्तव/दिव्य भारत

प्रतापगढ़। बाघराय थाने में ड्यूटी करने जा रहे होमगार्ड की घर के पास खेत में शव मिलने से हड़कंप मच गया, होमगार्ड की हत्या होने की जानकारी पर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है वहीं मौके की नजाकत को समझते हुए एसपी डॉक्टर अनिल कुमार भी मौके पर पहुंच जाते हैं।

मामला है प्रतापगढ़ में जेठवारा थाना इलाके के नगरिया गांव में सुबह होमगार्ड शिव राम पटेल का घर के पास खेत में शव मिलने से सनसनी फैल जाती है। मृतक होमगार्ड शिव राम बाघराय थाने में ड्यूटी करने के लिए निकला था,की उसकी किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या होने की जानकारी पर परिवार वाले भी मौके पर पहुंच जाते हैं,और मृतक होमगार्ड शिव राम का शव देखकर परिवार वालों का रो-रो कर बुरहाल हो जा रहा था।

आनन फानन मे होमगार्ड की शव मिलने की सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच जाती है और हर पहलू को देखते हुए जांच में जुट जाती है।

16 जातियों के 101 जोड़ों ने रचाया विवाह, उत्सव जैसा माहौल

- **राजा भइया के निर्देश पर सामूहिक विवाह में अबतक 1381 कन्याओं की शादी संपन्न**

अजीत प्रताप सिंह/दिव्य भारत

कुंडा प्रतापगढ़। सामाजिक समरसता और गरीब परिवारों के सहयोग के उद्देश्य से आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में इस वर्ष 101 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री कुंडा विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भइया के निर्देश पर यह आयोजन किया गया। राजा भइया यूथ ब्रिगेड और योगीराज देवरहा बाबा चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में 1995 से चले आ रहे इस सामूहिक विवाह में अब तक 1381 कन्याओं की शादी कराई जा चुकी है।इस वर्ष 24 मार्च 2025 को आयोजित 31वें सामूहिक विवाह में 16 जातियों के 101 जोड़ों ने सात फेरे लिए। 1995 में जब इस कार्यक्रम की शुरूआत हुई थी, तब केवल 11 कन्याओं की शादी कराई गई थी। लेकिन अब यह आयोजन बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिलता है। विवाह समारोह धूमधाम से मनाया गया, जहां नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

पूर्व सांसद एवं वर्तमान एमएलसी कुंवर अक्षय प्रताप सिंह (गोपाल जी) के मार्गदर्शन में राजा भइया यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने बारातियों के स्वागत में पूरी निष्ठा से सेवाएं दीं। आयोजन को भव्य और यादगार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी। एमएलसी गोपाल जी भी देर रात तक कार्यक्रम में मौजूद रहे और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

राजा भइया के प्रतिनिधि यूथ ब्रिगेड के सचिव हरिओम शंकर श्रीवास्तव और राजा भइया यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष इंद्रदेव पटेल ने सामूहिक विवाह को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह सहयोग और स्नेह ही इस अभियान की प्रेरणा और ताकत है। साथ ही, उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि सभी नवविवाहित जोड़ों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।

बेसिक शिक्षा विभाग गर्मी की छुट्टियों में समर कैंप का करेगा आयोजन

- **समर कैंप में निखरेंगी परिषदीय स्कूलों के बच्चों की प्रतिभा**
- **चुनिंदा विद्यालयों में चलाए जाएंगे समर कैंप, बच्चों को खेल के साथ ही कई अन्य गतिविधियों से जोड़ा जाएगा**

दिव्य भारत संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के बच्चे अब गर्मी की छुट्टियों में समर कैंप के जरिए खेल-खेल में पढ़ाई के साथ ही एक्स्ट्रा एक्टिविटीज से जुड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में बेसिक शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। 20 मई से 15 जून के बीच चुनिंदा विद्यालयों में समर कैंप आयोजित किए जाएंगे, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ खेलों, स्किल और नई-नई गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। सीएम योगी के निर्देश पर समर कैंप सुबह के समय शुरू होंगे और डेढ़ घंटे तक चलेंगे। इस दौरान बच्चों के समग्र विकास के लिए आनंददायक और रचनात्मक गतिविधियों पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा मित्र, अनुदेशक और शिक्षकों की देखरेख में कैंप का संचालन होगा, जिसमें एनजीओ और स्नातक वालंटियर्स भी सहयोग करेंगे। कैंप में बच्चों को खानपान की सुविधा भी मिलेगी। सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन के तहत गुड़ चिक्की, बाजरे का लड्डू, रामदाना लड्डू, गुड़-चना और लैया पट्टी जैसी पौष्टिक चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसका उद्देश्य बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हुए सीखने के लिए प्रेरित करना है। समर कैंप में फाउंडेशनल लिट्रेसी और न्यूमेरेसी (एफएलएन) पर आधारित गतिविधियों के साथ-साथ जीवन कौशल, व्यक्तित्व विकास, योग, खेलकूद, विज्ञान-तकनीक आधारित प्रयोग, कला-सांस्कृतिक कार्यक्रम और पर्यावरण जागरूकता जैसे विषय शामिल होंगे। यह बच्चों को नई दिशा देने का एक सुनहरा अवसर होगा। योगी सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 200 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया है। यह पहल न केवल बच्चों के शैक्षिक विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि उनकी छिपी प्रतिभाओं को निखारने में भी मददगार साबित होगी।

बेसिक शिक्षा विभाग के 16 फर्जी शिक्षक बर्खास्त

लखनऊ, (हि.स.)। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के संज्ञान में जैसे ही सीतापुर में 16 फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति का मामला आया, उन्होंने तुरंत विभाग के उच्च अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने इन सभी शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। बता दें कि यह फजीर्वाड़ा 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत जुलाई 2024 में हुई नियुक्तियों में सामने आया। जांच में पाया गया कि 16 शिक्षकों ने फर्जी टीईटी प्रमाण पत्रों और अन्य कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल की थी। सत्यापन के दौरान जब यह धोखाधड़ी उजागर हुई और मामला बेसिक शिक्षा मंत्री के संज्ञान में आया। उन्होंने विभाग को जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। जांच में बड़ा फजीर्वाड़ा उजागरसरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार, जिन 16 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द की गई हैं, उनमें बबलू यादव, रंजना, अभिषेक कुमार, विनोद कुमार, मनोज कुमार, अरविंद कुमार, गोपाल सिंह, जीतेंद्र कुमार, राहुल कुमार, अकबर शाह, प्रदीप कुमार यादव, दिनेश कुमार यादव, प्रमोद कुमार, भूपेंद्र सिंह, सुनील कुमार और ओमवीर सिंह के नाम शामिल हैं। इनमें अधिकांश के टीईटी प्रमाण पत्र और दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री की दो टूक बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने दो टूक कहा कि योगी सरकार किसी भी स्थिति में फजीर्वाड़े को सहन नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी विभागों में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है और आने वाले समय में यह अभियान और तेज होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ऐसे सभी फर्जी नियुक्तियों की जांच कर कार्रवाई जारी रहेगी। भविष्य में भी जो कोई गड़बड़ी करेगा, उसे इसी तरह कठोर दंड मिलेगा। योगी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी मुहिमयोगी सरकार लगातार सरकारी विभागों को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए कड़े फैसले ले रही है। इससे पहले भी कई जिलों में फर्जी नियुक्तियों को रद्द किया गया था और दोषियों पर कानूनी शिकंजा कसा गया था।